REPUBLIC DAY TABLEAU 2025

अध्याय 10

क्षमता निर्माण, जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम तथा अन्य सहायक कार्यक्रम

10.1 सूचना एवं जन जागरूकता (आई एंड पीए) कार्यक्रम

10.1.1 भारत बड़ी जल विद्युत सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। मंत्रालय ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुविधाजनक नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए व्यवस्थित रूप से काम किया है। पहल, लाभ और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को जनता तक पहुँचाने के लिए, सूचना का प्रसार और प्रचार आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आई एंड पीए कार्यक्रमों की अवधारणा तैयार की गई है और कार्यान्वयन के लिए विकसित किया गया है।

चित्र. 10.1

10.1.2 आई एंड पीए कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जागरूकता पैदा करना तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को विभिन्न मीडिया के माध्यम से समाज में व्यापक रूप से प्रसारित करना है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन सरकारी चैनलों जैसे (i) केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC) (ii) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC); (iii) दूरदर्शन; (iv) ऑल इंडिया रेडियो (AIR); (v) नवीकरणीय ऊर्जा के लिए राज्य नोडल विभाग/एजेंसियाँ; तथा (vi) गैर सरकारी संगठन/शैक्षणिक संस्थान आदि के माध्यम से किया जाता है, तथा मंत्रालय द्वारा तथा अन्य प्रासंगिक संस्थानों/संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व की प्रदर्शनियों में भागीदारी की जाती है।

10.1.3 वर्ष 2024 के दौरान मंत्रालय के कार्यक्रमों, योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं आदि पर वेबिनार, कार्यशाला जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अर्थव्यवस्था में ईंधन सेलों पर हाइड्रोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 136 08-04-2025 23:58:36

भागीदारी (आईपीएचई), ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीजीएच) और री-इन्वेस्ट नामक तीन सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों की कवरेज को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और पूरे कार्यक्रम अवधि के दौरान सोशल मीडिया पर ये शीर्ष ट्रेंडिंग में रहे। अक्षय ऊर्जा पर राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कार्यक्रमों/प्रदर्शनियों में मंत्रालय के लोगो द्वारा समर्थन दिया गया।

10.1.4 सूचना युग के बदलते परिदृश्य में मौजूदा कार्यक्रम को और अधिक कुशल और किफायती बनाने के लिए, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब आदि सहित नए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर स्वयं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता शामिल है, एक सोशल मीडिया सेल पहले से ही चालू है और नागरिकों को सटीक जानकारी सक्रिय रूप से प्रसारित करता है। यह सेल जनता तक प्रासंगिक जानकारी का प्रचार करने के लिए ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, स्पॉटिफाई और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर प्रासंगिक सामग्री वाले पॉडकास्ट उपलब्ध हैं। मीडिया सेल के फोलोअर बेस के अति विशिष्ट वर्ग में उद्योग और उपयोगकर्ता शामिल हैं। नागरिकों के साथ मजबूत जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने फीडबैक फ्राइडे जैसी पहलों को लागू किया है, जहां प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और क्विज या पहेलियाँ आयोजित की जाती हैं। साथ ही, चल रही योजनाओं से संबंधित सफलता की कहानियाँ साझा की जाती हैं।

10.2 मानव संसाधन विकास

10.2.1 एमएनआरई के मानव संसाधन विकास (एचआरडी) कार्यक्रम का उद्देश्य देश में योग्य और प्रशिक्षित मेनपावर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा शिक्षा और प्रशिक्षण को संस्थागत बनाना है। एचआरडी कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान और विकास और शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों और शोध विद्वानों को फेलोशिप प्रदान करके, उच्च अध्ययन और शोध पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने सहित सभी स्तरों पर मेनपावर के प्रशिक्षण का समर्थन करता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर पर उच्च डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अपने प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए अनुसंधान और विकास और शैक्षणिक संस्थानों को भी सहायता प्रदान की जाती है। एचआरडी योजना के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना, चालू करने, संचालन और रखरखाव के लिए वर्कफोर्स को प्रशिक्षित करने के लिए **सूर्यमित्र, वरुणमित्र, वायुमित्र और जलउर्जामित्र नामक कौशल विकास कार्यक्रम** शुरू किए गए।

मानव संसाधन विकास योजना के विभिन्न घटक इस प्रकार हैं:

क. सभी स्तरों पर कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर अल्पकालिक प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए शैक्षिक एवं अन्य प्रशिक्षण संगठनों को सहायता। कौशल विकास कार्यक्रम जैसे सौर पी.वी. तकनीशियन (सूर्यमित्र), सौर जल पम्पिंग तकनीशियन (वरुणमित्र), पवन ऊर्जा संयंत्र तकनीशियन (वायुमित्र) तथा लघु जल विद्युत संयंत्र तकनीशियन (जलऊर्जामित्र)।

ख. एम.एससी./एम.टेक/पीएचडी/पीडीएफ डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा फेलोशिप (एनआरईएफ) योजना।

ग. नवीकरणीय ऊर्जा में नवीन विचार के साथ अनुसंधान संस्थानों में काम करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिकों के लिए राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञान फेलोशिप योजना।

घ. प्रयोगशाला उन्नयन के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को सहायता।

ड. राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा इंटर्नशिप योजना (एनआरईआई)।

च. नवीकरणीय ऊर्जा पीठ

चित्र. 10.2

10.2.2 राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा फेलोशिप योजना

एमएनआरई ने एनआरईएफ योजना के तहत फेलोशिप या वजीफा प्रदान करके चयनित शैक्षणिक संस्थानों में चल रही फेलोशिप के माध्यम से अक्षय ऊर्जा में एमएससी, एम.टेक, पीएचडी पाठ्यक्रमों जैसे उच्च अध्ययन करने के लिए छात्रों और विद्वानों को अपना समर्थन जारी रखा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, एमएनआरई ने एनआरईएफ योजना के तहत चयनित शैक्षणिक संस्थानों में उच्च अध्ययन करने के लिए विद्वानों और छात्रों को 53 फेलोशिप (चल रही 41 फेलोशिप और नई 12 फेलोशिप) प्रदान करके अपना समर्थन जारी रखा, जिसमें 4 आरए/पीडीएफ, 33 पीएचडी और 16 एम.टेक फेलोशिप शामिल हैं। फेलोशिप भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी किए जाते हैं। फेलोशिप द्वारा समर्थित संस्थानों की सूची तालिका 10.1 में दी गई है

तालिका 10.1 : वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फेलोशिप के लिए समर्थित संस्थानों का विवरण

क्र. सं.	विभाग/संस्थान का नाम
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
2	अनुप्रयुक्त विज्ञान और मानविकी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय
3	ऊर्जा अध्ययन केंद्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
4	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
5	सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल), नई दिल्ली
6	ऊर्जा अध्ययन संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
7	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि
8	हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी विभाग, पॉडिचेरी विश्वविद्यालय
9	ऊर्जा विभाग, तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
10	राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान/एनआईटी जालंधर

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 138 08-04-2025 23:58:36

10.2.3 कौशल विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षण

(a) सौर पीवी तकनीशियन (सूर्यमित्र कौशल विकास) कार्यक्रम

सौर विद्युत क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए वर्कफोर्स विकसित करने के लिए मंत्रालय द्वारा 2015 में सौर पीवी तकनीशियन (सूर्यमित्र) प्रशिक्षण शुरू किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024–25 में, नाइस को 6400 सूर्यमित्रों का प्रशिक्षण आवंटित किया गया था। ये प्रशिक्षण नाइस द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सूचीबद्ध, देश भर के विभिन्न राज्यों में 427 प्रशिक्षण केंद्रों और साझेदार संगठनों के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं । वित्त वर्ष 2024–25 में, 865 सूर्यमित्रों को प्रशिक्षित किया गया और 6164 सूर्यमित्रों का प्रशिक्षण चल रहा है। दिसंबर, 2024 तक कुल 57372 सूर्यमित्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(b) वायुमित्र कार्यक्रम:

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वायुमित्र कौशल विकास कार्यक्रम (वीएसडीपी) शुरू किया है, जिसमें राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नीवे), चेन्नई को पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुशल और प्रशिक्षित मैनपावर तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2021–22 से 2024–25 की अवधि के दौरान 5000 से अधिक प्रशिक्षु तैयार करना है। दिसंबर, 2024 तक वीएसडीपी के तहत कुल 2351 उम्मीदवारों (281 प्रशिक्षक और 2070 प्रतिभागी) को प्रशिक्षित किया गया। सभी प्रतिभागियों का मूल्यांकन स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स (एससीजीजे) द्वारा किया गया है और उन्हें भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एसएसडीई) के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में 90 प्रतिभागियों के साथ टीओपी कार्यक्रमों के तीन बैच चल रहे हैं। कार्यक्रम से संबंधित विवरण जैसे मास्टर ट्रेनर, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण भागीदार, प्रशिक्षण केंद्र, प्रतिभागियों का प्रशिक्षण, प्रतिभागियों की पात्रता मानदंड, कार्यक्रम की तिथियां और कार्यक्रम आदि एक विशेष वेब पोर्टल (https://vsdp.niwe.res.in/) पर उपलब्ध हैं।

(c) जलऊर्जामित्र कार्यक्रम:

मंत्रालय ने लघु जलविद्युत परियोजनाओं के रखरखाव के लिए तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए जल-ऊर्जामित्र कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 5 वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक की अवधि के लिए 1700 से अधिक कुशल मेनपावर विकसित करना है। जल एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की इस कार्यक्रम का समन्वय कर रहा है। एचआरईडी, आईआईटी रुड़की ने जल ऊर्जामित्र कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण देने के लिए 8 प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) को सूचीबद्ध किया है। दिसंबर 2024 तक 455 उम्मीदवारों और 54 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 150 जल ऊर्जामित्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

वर्ष 2015-16 से 2024–25 (दिसंबर 2024) तक सूर्यमित्र, वायुमित्र और जलऊर्जामित्र की राज्य-वार प्रगति तालिका 10.2 में दर्शाई गई है।

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 139 08-04-2025 23:58:36

तालिका-10.2 कौशल विकास कार्यक्रमों अर्थात सूर्यमित्र, जलऊर्जामित्र और वायुमित्र कार्यक्रमों के अंतर्गत 31 दिसंबर 2024 तक प्रशिक्षित और रोजगार प्रदान किए गए मैनपावर की राज्यवार सूची

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूर्यमित्रों की संख्या		जलऊर्जामित्रों की संख्या		वायुमित्रों की संख्या	
		प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त	प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त	प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	2204	1240	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर)	60	21	29	0	0	0
4	असम (पूर्वोत्तर)	1662	969	0	0	0	0
5	बिहार	1886	1157	0	0	0	0
6	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	298	166	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	2267	1216	0	0	0	0
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	702	336	0	0	0	0
10	गोवा	321	202	0	0	0	0
11	गुजरात	3397	1990	0	0	210	80
12	हरयाणा	1621	679	0	0	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	534	182	44	0	0	0
14	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	813	262	0	0	0	0
15	झारखंड	906	487	0	0	0	0
16	कर्नाटक	1962	806	53	25	30	0
17	केरल	975	501	0	0	0	0
18	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	30	16	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	30	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	5468	2580	0	0	120	93
21	महाराष्ट्र	4864	2522	0	0	540	195
22	मणिपुर (पूर्वोत्तर)	150	50	0	0	0	0
23	मेघालय (पूर्वोत्तर)	30	022	0	0	0	0
24	मिजोरम (पूर्वोत्तर)	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड (पूर्वोत्तर)	60	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	2667	1078	180	146	0	0
27	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	122	19	0	0	0	0

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूर्यमित्रों की संख्या		जलउर्जामित्रों की संख्या		वायुमित्रों की संख्या	
		प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त	प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त	प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त
28	पंजाब	703	299	0	0	0	0
29	राजस्थान	4332	2538	0	0	330	113
30	सिक्किम (पूर्वोत्तर)	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	3920	2057	59	0	840	565
32	तेलंगाना	3838	2172	0	0	0	0
33	त्रिपुरा (पूर्वोत्तर)	178	57	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	5805	2171	0	0	0	0
35	उत्तराखंड	1148	586	90	77	0	0
36	पश्चिम बंगाल	4419	2119	0	0	0	0
कुलः	57372	28500	455	248	2070	1046	
कुल प्रशिक्षितः 59897 **कुल रोजगार प्राप्तः** 29794 (49.74%)							

10.2.4 राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा इंटर्नशिप योजना (एनआरईआई)

राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा इंटर्नशिप (एनआरईआई) कार्यक्रम के तहत, मंत्रालय द्वारा भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थानों या विश्वविद्यालयों में नामांकित स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों या शोधार्थियों को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जाता है, ताकि वे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों/नीतियों/योजनाओं को समझ सकें। वित्त वर्ष 2024-25 में, बी.टेक, एम.टेक, एलएलबी, एम.एससी, एमबीए स्ट्रीम के 17 छात्रों ने एमएनआरई और इसके संस्थानों में इंटर्नशिप पूर्ण की।

10.2.5 प्रयोगशाला उन्नयन के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को सहायता

संस्थानों को नवीकरणीय ऊर्जा पाठ्यक्रमों में शिक्षा/प्रशिक्षण शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, प्रयोगशाला उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा में एम.एस.सी., एम.टेक., पीएच.डी. पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके। स्वीकृत अनुदान 50 लाख रुपये में से लगभग 50% धनराशि निम्नलिखित संस्थानों को प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की गई।

i. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
ii. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
iii. कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि
iv. जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

10.3 मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पहल

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने मिशन कर्मयोगी के व्यापक दृष्टिकोण से निर्देशित अपने क्षमता निर्माण प्रयासों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सितंबर 2020 में शुरू किया गया मिशन कर्मयोगी, जिसे राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) के रूप में भी जाना जाता है, को योग्यता-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम

से भारत की सिविल सेवाओं को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नियमों से भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करके, मिशन संरचित सीखने और निरंतर प्रदर्शन विश्लेषण के माध्यम से प्रभावी शासन और सेवा वितरण को बढ़ावा देता है।

चित्र. 10.3

10.3.1 iGoT प्लेटफॉर्म पर सीखना

एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईजीओटी) कर्मयोगी मंच, ऑनलाइन, ऑफलाइन और मिश्रित सहित विविध शिक्षण मोड को प्रस्तुत करते हुए, मंत्रालय में इन प्रयासों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों की 100% ऑनबोर्डिंग हासिल की, जिसमें नियमित और संविदा दोनों कर्मचारी शामिल हैं, सभी अधिकारियों की भागीदारी विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से रही है। कुल 4,073 शिक्षण घंटे लॉग किए गए हैं, और मंत्रालय के कार्मिकों ने 2,885 पाठ्यक्रम पूरे करने के साथ 4,185 पाठ्यक्रमों में सफलतापूर्वक नामांकन किया है। यह लगभग 65.9% की पूर्णता दर को दर्शाता है। उल्लेखनीय जुड़ाव में 82. 75% उपयोगकर्ताओं द्वारा कम से कम एक कोर्स पूरा करना, 56.89% द्वारा पाँच या अधिक पाठ्यक्रम पूरे करना शामिल है, जो एमएनआरई के भीतर एक मजबूत शिक्षण संस्कृति को प्रदर्शित करता है।

10.3.2 राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (एनएलडब्ल्यू) 2024

अक्टूबर 2024 में, क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) और कर्मयोगी भारत (केबी) ने संयुक्त रूप से सिविल सेवकों के लिए सतत शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सप्ताह का शिक्षण अभियान, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 19 अक्टूबर 2024 को डॉ। अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में सुबह 10 बजे किया गया। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह में अधिकारियों की महत्वपूण र्ा भागीदारी देखी गई, जिसमें 32% ने न्यूनतम चार घंटे की शिक्षा पूरी की। मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरण ाीय ऊर्जा में एआई, पराली जलाने और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में बोली और निविदा जैसे डोमेन विषयों को कवर करने वाली पांच भौतिक कार्यशालाओं का आयोजन किया। मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए 'माइंडफुलनेस' कार्यशाला भी आयोजित की।

10.3.3 वार्षिक क्षमता निर्माण योजना एवं प्रशिक्षण कैलेंडर

एक व्यापक वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) का निर्माण एमएनआरई के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है। क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के सहयोग से, मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) और प्रशिक्षण कैलेंडर को अंतिम रूप दिया, जिसमें कार्यात्मक, व्यवहारिक और डोमेन दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। एसीबीपी को दिसंबर 2024 में मंजूरी दी गई थी, जिसमें कर्मचारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर अब तिमाही सीखने के लक्ष्य उपलब्ध हैं। इस योजना में सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में डोमेन-विशिष्ट पाठ्यक्रम शामिल हैं।

अपने मंत्रालय को जानें (केवाईएम मॉड्यूल)

मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एक प्रमुख गतिविधि मंत्रालय/विभाग/संगठनों में तैनात कर्मचारियों के लिए लघु, ऑनलाइन, प्रेरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के रूप में केवाईएम मॉड्यूल का विकास करना है। मंत्रालय का एक व्यापक केवाईएम मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, जिसमें नीतियों, योजनाओं आदि का इतिहास और नीतियों, योजनाओं आदि की सूची 11 मॉड्यूलों में विस्तृत रूप से दर्शाई गई है।

10.3.4 मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन

मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 13 से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था "उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना - जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना"। इस विषय के अंतर्गत उप-विषयों/स्तंभों में से एक है, "हरित अर्थव्यवस्था में अवसर" जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कौशल और रोजगार सृजन शामिल है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 22 जुलाई, 2024 को एक कार्य समूह का गठन किया था, जिसमें सौर, पवन और जैव ऊर्जा उद्योग संघों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें शिक्षा जगत/थिंक टैंक के प्रतिनिधि और अन्य मंत्रालयों और सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे। कार्य समूह द्वारा तैयार अवधारणा नोट को सभी हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर अंतिम रूप दिया गया और राज्यों के साथ साझा किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कार्यशालाएं 21 अगस्त, 2024 को व्यक्तिगत रूप से और 28 अगस्त, 2024 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गईं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से अवधारणा नोट पर इनपुट प्राप्त हुए। अवधारणा नोट पर चर्चा करने और नौकरियों की संख्या पर पहुंचने की कार्यप्रणाली पर आम सहमति बनाने के लिए कार्य समूह की कई बैठकें हुईं। सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए उप-समूह बनाए गए

इस पृष्ठभूमि नोट को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अलग-अलग राज्य फीडबैक नोट्स और राज्य-विशिष्ट नोट्स तथा उनमें प्रस्तुत महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि की समीक्षा के बाद संकलित किया गया है। विस्तृत पृष्ठभूमि नोट में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है: (i) तैनाती और कौशल में तेजी लाने के लिए चल रहे कार्यक्रमों की वर्तमान पहल और परिणाम (ii) चुनौतियाँ और संभावित समाधान (iii) सर्वोत्तम अभ्यास, (iv) प्राथमिकता वाले क्षेत्र और आगे का रास्ता (v) परिणाम, अपेक्षित समयसीमा और जिम्मेदारियाँ। राज्यों और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव की ओर से 14 दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुतियाँ दी गईं। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 38 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होंगे।

10.4 ई-गवर्नेंस/सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पहल

10.4.1 मंत्रालय का लक्ष्य आईटी उपकरणों के उपयोग के माध्यम से अपनी सभी गतिविधियों को डिजिटल बनाना है। एमएनआरई ने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत परिचालन में पारदर्शिता और हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किए हैं और उनका रखरखाव कर रहा है:

a) **मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://mnre.gov.in/):** मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट काs SWAAS (सुरक्षित, स्केलेबल, सुगम्य (सुलभ) क्लाउड सेवा) प्लेटफॉर्म में पुन: डिजाइन और पुनर्विकसित किया गया है। नई वेबसाइट अक्टूबर 2023 में लाइव की गई थी। यह अपनी सभी योजनाओं, वास्तविक उपलब्धियों और प्रभाग अधिकारियों की जानकारी के साथ एक द्विभाषी वेबसाइट (हिंदी और अंग्रेजी) है।

b) **रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल (https://solarrooftop.gov.in/):** आवासीय उपभोक्ताओं के लिए सरलीकृत प्रक्रिया वाला एक ऑनलाइन पोर्टल, जिससे उन्हें स्वयं या अपनी पसंद के वेंडर के माध्यम से रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने की सुविधा मिलती है। इस पोर्टल को रूफटॉप सोलर कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विकसित किया गया है। पोर्टल को DBT SANDES] PRAYAS और NGO DARPAN के साथ एकीकृत किया गया है।

c) **मानव संसाधन विकास (HRD) पोर्टल (https://hrd.mnre.gov.in):** पांच अलग-अलग योजनाओं के तहत देश में योग्य और प्रशिक्षित वर्कफोर्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा शिक्षा और प्रशिक्षण को संस्थागत बनाने के लिए विकसित एक पोर्टल। लाभार्थी निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन/प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं:

i. नवीकरणीय ऊर्जा में अल्पकालिक प्रशिक्षण और कौशल विकास
ii. नवीकरणीय ऊर्जा में उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए फेलोशिप
iii. नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का संवर्धन
iv. नवीकरणीय ऊर्जा अध्यक्ष
v. राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा इंटर्नशिप कार्यक्रम

d) **सीसीडीसी (रियायती सीमा शुल्क प्रमाणपत्र) पवन (https://ccdcwind.gov.in/):** यह पोर्टल पवन टर्बाइनों के विनिर्माण के लिए आवश्यक घटकों के आयात के लिए रियायती सीमा शुल्क प्रमाणपत्र जारी करने के लिए है।

e) **जैव ऊर्जा पोर्टल (https://biourja.mnre.gov.in/):** यह पोर्टल निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने और संसाधित करने के लिए विकसित किया गया है"

i. शहरी, औद्योगिक, कृषि अपशिष्ट/अवशेषों और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा देश में चीनी मिलों और अन्य उद्योगों में बायोमास आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देना।

f) **बायोगैस पोर्टल (https://biogas.mnre.gov.in/):** यह लाभार्थियों के लिए छोटे और मध्यम बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए आवेदन जमा करने हेतु एक केंद्रीय पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से स्थापना की प्रक्रिया और उसके बाद इंस्टॉलर और निरीक्षकों के लिए निरीक्षण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है। इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया जा रहा है।

g) **अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) पोर्टल (https://serviceonline.gov.in/dbt/):** आर एंड डी पोर्टल नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित आर एंड डी प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने और प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है।

h) **पीएम कुसुम पोर्टल (https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html):** यह पोर्टल पीएम कुसुम योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए विकसित किया गया है, जो किसानों के लिए है।

i) **सौर स्ट्रीट लाइट पोर्टल (https://ssl.mnre.gov.in/):** इस पोर्टल को सौर ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम चरण III के अंतर्गत सौर स्ट्रीट लाइटों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विकसित किया गया है।

j) **अक्षय ऊर्जा पोर्टल (https://akshayurja.gov.in/):** यह पोर्टल अक्षय ऊर्जा क्षमता, स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता और उत्पादन जैसे अक्षय ऊर्जा डेटा के लिए एक केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है। यह पोर्टल सौर, पवन, लघु जलविद्युत, जैव ऊर्जा और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों और ऑफ-ग्रिड घटकों

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 144 08-04-2025 23:58:36

के संबंध में विद्युत क्षमता, स्थापित क्षमता और विद्युत उत्पादन के बारे में डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करने जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।

k) **भारतीय अक्षय ऊर्जा विचार विनिमय पोर्टल (IRIX) (https://iriñ-gov-in):** प्त्प् वैश्विक अक्षय ऊर्जा समुदाय के लिए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विचार, नवाचार और इनक्यूबेट करने के लिए एक वास्तविक समय विचार विनिमय मंच है। यह विचारों के आदान-प्रदान, ज्ञान साझा करने और अक्षय ऊर्जा संसाधनों से संबंधित संभावित समाधान खोजने को प्रोत्साहित करता है।

l) **एएलएमएम पोर्टल:** पोर्टल को एमएनआरई के स्वीकृत मॉडलों और सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल के विनिर्माताओं के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियात्मक ढांचे का प्रबंधन करने के लिए विकसित किया जा रहा है। यह विनिर्माताओं को नए अनुप्रयोगों के मॉड्यूल द्वारा एएलएमएम सूची में अपने पीवी उत्पादों को शामिल करने, मौजूदा सुविधाओं में अतिरिक्त मॉडल जोड़ने, एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित करने, सह-एएलएमएम और नवीनीकरण जोड़ने में सक्षम करेगा।

m) **सौर ऊर्जा पोर्टल:** यह पोर्टल सौर ऊर्जा परियोजना डेवलपर्स को प्लग एंड प्ले मॉडल में परियोजनाएं स्थापित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। यह "सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास" योजना के तहत बनाए जा रहे सोलर पार्कों का विवरण एकत्र करेगा। यह "इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (InSTS) GEC-II योजना" के तहत राज्यवार वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी भी करता है।

n) **इंट्रा एमएनआरई:** पोर्टल को एमएनआरई परिसर में उपयोग की जा रही सेवाओं जैसे कि इन्वेंट्री का प्रबंधन, आईटी संपत्ति, कैंटीन, कॉन्फ्रेंस रूम बुकिंग, वाहन प्रबंधन आदि के प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। कॉन्फ्रेंस रूम और वाहन बुकिंग मॉड्यूल पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं। बजट और वास्तविक उपलब्धियों (समग्र, प्रभाग-वार और योजना-वार) के विवरण के लिए एमएनआरई अधिकारियों के लिए भूमिका आधारित डैशबोर्ड विकसित किए जा रहे हैं।

o) **गति शक्ति:** इस पोर्टल को पूरे भारत में सौर, पवन, हाइब्रिड (सौर और पवन), सौर पार्क, सौर पीवी विनिर्माण संयंत्रों के अंतर्गत बड़े पैमाने की परियोजनाओं की लेयर और कोओर्डिनेट्स का मानचित्रण करने के लिए विकसित किया गया है।

p) **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन पोर्टल:** एनजीएचएम पोर्टल को वैश्विक हरित हाइड्रोजन हब बनने की दिशा में भारत की यात्रा में रुचि रखने वालों के लिए सूचना और डेटा प्रसार के केंद्रीय बिंदु के रूप में विकसित किया जा रहा है।

q) **ई-एचआरएमएस:** ई-एचआरएमएस कार्मिक प्रबंधन गतिविधियों जैसे छुट्टी, पोस्टिंग, पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा पुस्तिका का रखरखाव आदि के लिए एक सामान्य अनुप्रयोग उपकरण है। यह मानव संसाधन प्रक्रियाओं को स्वचालित और डिजिटल बनाता है, जिससे सरकारी संगठन के भीतर दक्षता और पारदर्शिता बढ़ती है। यह पदोन्नति, स्थानांतरण/पोस्टिंग, भूमिका प्रबंधन, बिल प्रतिपूर्ति, छुट्टी के आवेदन, परिपत्र/ओएम/आदेश आदि जैसे विभिन्न मानव संसाधन-संबंधित कार्यों तक पहुँचने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है। इसे डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

r) **ई-ऑफिस:** कार्यालय में कागज रहित कार्य की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मंत्रालय ने ई-ऑफिस को पूरी तरह से लागू किया है, जिसका उद्देश्य फाइलों और रसीदों/पत्रों की प्रभावी प्रोसेसिंग और ऑनलाइन मूवमेंट है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज के मूल स्वरूप को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान देना है, जिससे अंततः पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही और तेजी से निर्णय लेने जैसे वांछनीय मूल्य सामने आएंगे।

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 145 08-04-2025 23:58:36

10.4.1.1 **सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023/साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण**

एमएनआरई (आईटी) प्रभाग ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान दिनांक 16.08.2024 से 15.11.2024 तक की गतिविधियों का आयोजन किया, जैसा कि सतर्कता प्रभाग से प्राप्त 20.08.2024 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में उल्लिखित है। रणनीतिक फोकस शिकायत निपटान को सुव्यवस्थित करने, दिशा-निर्देशों और मैनुअल को संशोधित करने और आईटी और साइबर सुरक्षा जागरूकता को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर था।

अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गईं:

1. **इंट्रा एमएनआरई पोर्टल पर सतर्कता मॉड्यूल का विकास**

   इंट्रा एमएनआरई पोर्टल में मासिक सतर्कता रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया था। यह मॉड्यूल सतर्कता गतिविधियों से संबंधित व्यापक मासिक सारांश तैयार करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, सतर्कता से संबंधित कार्यों में शामिल एमएनआरई कर्मियों के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव सुनिश्चित करने के लिए पहुँच और नेविगेशन को सुव्यवस्थित करने के लिए पोर्टल में परिवर्तन शामिल किए गए हैं।

2. **प्रशिक्षण सत्र/वेबिनार आयोजित किए गए:**

   सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आईटी सेल द्वारा दो प्रशिक्षण आयोजित किए गए, एक 7 अक्टूबर, 2024 को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण पर और दूसरा 25 अक्टूबर, 2024 को ई-ऑफिस संस्करण 6 पर।

10.4.2 **सतर्कता:** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) का सतर्कता प्रभाग सीवीसी/डीओपीटी दिशा-निर्देशों के अनुसार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को संभालता है। प्रभाग दो सीपीएसयू अर्थात् भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी) के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की भी जांच करता है, तथा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संगठनों अर्थात् तीन स्वायत्त निकायों में सतर्कता कार्य की निगरानी करता है: राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस), राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नीवे), और सरदार स्वर्ण राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान (एसएसएस-नीबे)। सतर्कता प्रभाग को मंत्रालय के अधिकारियों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) और अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) को बनाए रखने और उनकी जांच करने का कार्य भी सौंपा गया है।

वर्ष 2024 के दौरान सतर्कता प्रभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों की लागू नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की गई तथा जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया गया, वहां आवश्यक कार्रवाई की गई।

मंत्रालय में 28 अक्टूबर, 2024 से 3 नवंबर, 2024 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024' मनाया गया। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय 'राष्ट्र की समृद्धि के लिए संस्कृति से सत्यनिष्ठा' था। सप्ताह के दौरान, सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 से संबंधित बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए, निवारक सतर्कता पर एक व्याख्यान भी आयोजित किया गया। सप्ताह के दौरान वाद-विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि सहित विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, साइबर सुरक्षा पर एक प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया।

जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों के बारे में नागरिकों एवं अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए।

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 146 08-04-2025 23:58:36

चित्र.10.4: निवारक सतर्कता पर कार्यशाला

चित्र.10.5: सतर्कता प्रतिज्ञा 202

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का पुस्तकालय नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संदर्भ केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में पुस्तकालय में 12,814 पुस्तकें (उपहार में दी गई पुस्तकों सहित) उपलब्ध हैं, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विज्ञान, सतत विकास, इतिहास, समाजशास्त्र, भारतीय साहित्य, कंप्यूटर विज्ञान आदि जैसे विविध विषय शामिल हैं। पुस्तकालय के संग्रह में भोजन, खाना पकाने, मूर्तिकला, चित्रकला, पर्वतारोहण आदि जैसी सामान्य रुचि की पुस्तकें भी शामिल हैं।

ii. मंत्रालय में गठित पुस्तकालय समिति, पुस्तकालय द्वारा खरीद के लिए पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि की जांच करती है तथा सिफारिश करती है।

iii. पुस्तकालय ने वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में 33 पत्रिकाओं को सब्सक्राइब किया गया है। इसके अलावा, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में 23 समाचार पत्रों को भी सब्सक्राइब किया गया है। पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं के लिए लाइब्रेरी कैटलॉग तक पहुँचने, सर्कुलेशन (इश्यू-रिटर्न) और सदस्यता प्रबंधन आदि के लिए पुस्तकालय क्लाउड-आधारित लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ई-ग्रंथालय संस्करण 4.0 का उपयोग कर रहा है।

10.4.4 सूचना का अधिकार अधिनियम

मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), केंद्रीय सूचना आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित कर रहा है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया/अन्य विवरण एमएनआरई की वेबसाइट www.mnre.gov.in पर उपलब्ध हैं।

दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान प्राप्त, निपटाए गए तथा लंबित आरटीआई आवेदन या प्रथम अपील के संदर्भ में प्रगति रिपोर्ट निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए मंत्रालय के आरटीआई आवेदन / अपील

वस्तु	प्राप्त	निपटारा कर दिया गया	31.03.2024 तक लंबित
आरटीआई आवेदन	643	603	40
प्रथम अपील	36	30	06

तृतीय पक्ष पारदर्शिता लेखापरीक्षा सक्रिय प्रकटीकरण मंत्रालय की वेबसाइट (www.mnre.gov.in) पर अपलोड किया गया था, जिसमें आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत आवश्यक जानकारी शामिल थी। इसमें आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी) के तहत आवश्यक विभाग के कार्यों के साथ-साथ उसके पदाधिकारियों आदि का विवरण भी शामिल है।

मंत्रालय ने आरटीआई आवेदनों और प्रथम अपीलों का जवाब देने के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों (एफएए) को नियुक्त किया है। सीपीआईओ और एफएए की सूची निम्नलिखित तालिका में दी गई है। आरटीआई का नोडल अधिकारी सभी भौतिक और ऑनलाइन आवेदनों का समन्वय करता है और सीपीआईओ और एफएए को निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने के लिए तैयार करता है।

कार्य के पुन: आवंटन के आधार पर नामित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों (एफएए) की सूची:

क्र.सं.	विषय	सीपीआईओ का नाम एवं पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	एफएए का नाम और पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती
1	i. अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त ईएफसी/एसएफसी/कैबिनेट नोट्स/अवधारणा कागजात पर टिप्पणियाँ; ii. नीति आयोग की निगरानी से संबंधित मामले, जिसमें वार्षिक पीएम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर समीक्षा और आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) शामिल है; iii. ई-समीक्षा पोर्टल और अन्य पोर्टलों को नियमित रूप से अद्यतित करना, जिसमें बजट घोषणाओं को अद्यतित करना भी शामिल है।	शोभित श्रीवास्तव, वैज्ञानिक 'ई'	जे. राजेश कुमार, आर्थिक सलाहकार (ईए)
2	राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से संबंधित सभी मामले	शोभित श्रीवास्तव, वैज्ञानिक 'ई'	डॉ. पंकज सक्सेना, वैज्ञानिक 'जी
3	प्रशासन-I	अरुणव सेनगुप्ता, अवर सचिव	पंकज गुप्ता, उपसचिव
4	प्रशासन -II	अरुणव सेनगुप्ता, अवर सचिव	समीर कुमार दास, उपसचिव

क्र.सं.	विषय	सीपीआईओ का नाम एवं पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	एफएए का नाम और पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)
5	i. मासिक अक्षय ऊर्जा प्रगति डेटा संकलन और अद्यतन; ii. मासिक कैबिनेट अ.शा. पत्र तैयार करना; iii. माननीय मंत्री की बैठकों के अवलोकन के लिए संक्षिप्त विवरण तैयार करना; iv. स्थायी समिति/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन/आरपीएम बैठक/अन्य समीक्षा बैठक आदि की बैठकों के लिए पृष्ठभूमि नोट्स/पीपीटी तैयार करना; v. माननीय प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण/माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण आदि के लिए इनपुट प्रदान करना;	आयुष गुप्ता, वैज्ञानिक 'सी'	डॉ. पंकज सक्सेना, वैज्ञानिक 'जी
	vi. वर्षांत समीक्षा/पीआईबी के लिए संक्षिप्त लेखन तैयार करना; vii. वार्षिक रिपोर्ट के लिए इनपुट, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र का अध्याय शामिल है; viii. विजन दस्तावेज की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)		
6	सौर–ऑफ ग्रिड, सौर सिटी	आयुष गुप्ता, वैज्ञानिक 'सी'	जे.के. जेठानी वैज्ञानिक 'एफ'
7	राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन	प्रशांत द्विवेदी वैज्ञानिक 'सी	सुजीत पिल्लई, वैज्ञानिक 'एफ'
8	आरपीओ सहित नीति और विनियामक मामले (2022–2023 से आगे अनुपालना निगरानी), आरईसी नीति, विनियामक अनुपालना निदेशालय	कौशिक गोस्वामी, डीजीएम	जे के जेठानी, वैज्ञानिक 'एफ
9	ऊर्जा भंडारण (परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर मिशन); ई-मोबिलिटी [नेशनल बोर्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनबीईएम)]	पी.एन.बी.वी चालपति राव, वैज्ञानिक 'डी'	कुलदीप राणा, वैज्ञानिक 'ई'
10	रूफटॉप सौर; सोलर सिटी	सुमन कुमार, अवर सचिव	मनीष सिंह बिष्ट, वैज्ञानिक 'डी'
11	सेकी से संबंधित सभी मामले	सुमन कुमार, अवर सचिव	संजय कर्णधार, वैज्ञानिक 'ई'
12	पीएम गति शक्ति	पी.वी. तरुण साकेत, वैज्ञानिक 'सी'	कुलदीप राणा, वैज्ञानिक 'ई'

क्र.सं.	विषय	सीपीआईओ का नाम एवं पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	एफएए का नाम और पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती
13	सोलर पार्क योजना	पी.वी. तरुण साकेत, वैज्ञानिक 'सी'	ए. एस. परीरा, वैज्ञानिक 'ई'
14	एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड (ओएसओडब्लूओजी)	पी.वी. तरुण सकेत, वैज्ञानिक 'सी'	अरुण कुमार, वैज्ञानिक ड
15	i) ट्रांशमिशन ii) ग्रीन एनर्जी कारीडोर	हिमांशु प्रभाकर, अवर सचिव	तरुण सिंह, वैज्ञानिक 'ई
16	पुरानी योजनाएं (सौर शहर एवं ग्रीन बिल्डिंग; एनपीटी बिल्डिंग, एनटीपीसी-ईपीसी परियोजनाएं); कोणार्क योजना का सौरीकरण, पीएमडीपी के अंतर्गत लद्दाख में सौर परियोजनाएं	अरविंद एम.ए., वैज्ञानिक 'डी'	ए.एस. परीरा, वैज्ञानिक 'ई'
17	वीजीएफ योजना, रूफटॉप पीवी और लघु सौर विद्युत उत्पादन कार्यक्रम (आरपीएसएसजीपी); जीबीआई योजना	सचिन मीणा, वैज्ञानिक 'सी'	अरुण कुमार, वैज्ञानिक 'डी'
18	प्रयोगशाला नीति और मानक गुणवत्ता नियंत्रण	हीरेन सी बोराह, वैज्ञानिक 'इ'	
19	बायोमास विद्युत योजनाएँ और नीतियां, बायो ऊर्जा मिशन, बायोमास कुक-स्टव, बायोमास गैसीफायर से संबंधित सभी कार्य, नीबे से संबंधित सभी प्रशासनिक और वित्तीय मामले	एस. के. शाही, वैज्ञानिक 'ई'	डॉ. संगीता एम. कस्तूरे, वैज्ञानिक 'जी'
20	अपशिष्ट से ऊर्जा	विकास कुमार उपाध्याय वैज्ञानिक श्सीश	गौरव मिश्रा, वैज्ञानिक, 'एफ'
21	उत्तर-पूर्व में अक्षय ऊर्जा का विकास	हीरेन सी. बोराह, वैज्ञानिक 'ई'	जे. के. जेठानी, वैज्ञानिक 'एफ'
22	बायोगैस विद्युत (ऑफ-ग्रिड कार्यक्रम), राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम, बायोगैस प्रशिक्षण केंद्र	पी. एम. बारिक, वैज्ञानिक 'डी'	एस.आर. मीणा, वैज्ञानिक 'ई'
23	इरेडा के सभी प्रशासनिक मामले	सुनीता सजवान, अवर सचिव	तरुण सिंह, वैज्ञानिक 'ई'
24	पीएम कुसुम योजना	यौरव यादव, अवर सचिव	निखिल गक्खड, वैज्ञानिक 'डी'
25	आईटीईसी इनोवेशन सेंटर सहित मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण	गितांजलि बीरमानी, अवर सचिव	वसंता वी. ठाकुर, वैज्ञानिक 'ई'
26	पवन ऊर्जा (अपतटीय), लघु पवन, पवन ऊर्जा(तटीय); पुन:शक्तिकरण और हाइब्रिड नीतियाँ; सीसीडीसी पवन और सौर, नीवे के सभी प्रशासनिक और वित्तीय मामले	राहुल रावत, वैज्ञानिक 'डी'	पी. के. दास, वैज्ञानिक 'ई'

क्र.सं.	विषय	सीपीआईओ का नाम एवं पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	एफएए का नाम और पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)
27	अनुसंधान एवं विकास (पवन, सौर, बायोमास, हाइड्रोजन और बैटरी सहित), नई प्रौद्योगिकियां (भू-तापीय, महासागर/ज्वारीय ऊर्जा)	प्रिया, वैज्ञानिक 'डी'	अनिल कुमार, वैज्ञानिक 'ई'
28	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)	संजय प्रकाश भगत वैज्ञानिक 'सी'	प्रिया, वैज्ञानिक 'डी'
29	पुरानी योजनाएँ (द्वीपों का हरितीकरण, सौर थर्मल, गिर वन सौरीकरण); तटीय क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल	अनिल कुमार, वैज्ञानिक 'ई'	डॉ. ए. के. त्रिपाठी, वैज्ञानिक 'जी'
30	सीपीएसयू सरकारी उत्पादक योजना; केनाल टॉप सौर योजना; सौर विनिर्माण योजना; रिन्युएबल इंडस्ट्री प्रमोशन एंड फसिलिटेशन बोर्ड (आरईआई पीएफबी); उच्च दक्षता सौर मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना; दिशानिर्देशों के समाधान के लिए समन्वय एवं मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी)	मोहम्मद अजमल मंसूरी, वैज्ञानिक 'सी'	संजय कर्णधर, वैज्ञानिक 'ई'
31	एएलएमएम सेल: सौर विनिर्माता एवं डेवलपर के मामले	अरुण कुमार चौधरी, वैज्ञानिक 'सी'	संजय कर्णधार, वैज्ञानिक 'ई'
32	लघु जलविद्युत परियोजनाएँ; पीएम का लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा पहल पैकेज; जम्मू और कश्मीर के लिए पीएम विकास एवं पुनर्निर्माण पैकेज 2015	राजकुमार भावरिया, वैज्ञानिक 'सी'	एस. के शाही, वैज्ञानिक 'ई'
33	जलवायु परिवर्तन और एमओईएफ - सीसी के साथ समन्वय	तरुण वलेचा, वैज्ञानिक 'सी'	सुमन चंद्रा, निदेशक
34	सर्कुलर इकोनॉमी	तरुण वलेचा, वैज्ञानिक 'सी'	कुलदीप राणा, वैज्ञानिक 'ई'
35	आई एवं पीए; मीडिया/ सोशल मीडिया	ए.के. मनीष, अवर सचिव	सुमन चंद्रा, निदेशक
36	अक्षय ऊर्जा पत्रिका	ए.के. मनीष, अवर सचिव	डॉ. ए. के. त्रिपाठी, वैज्ञानिक 'जी'
37	सतर्कता; लोकपाल और लोकायुक्त	सौरभ मुखर्जी, अवर सचिव	समीर कुमार दास, उपसचिव
38	राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम)	ए. एस. परीरा, वैज्ञानिक 'ई'	सौरभ मुखर्जी,
39	अंतर्राष्ट्रीय संबंध (आईआर) और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग; अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और बहुपक्षीय पहल; जी-20	अवर सचिव	आसिम कुमार, निदेशक
40	कानूनी सेल	ए. के. सिंह, अवर सचिव	पंकज गुप्ता, उपसचिव
41	संसद कार्य/संसद से संबंधित सभी मामले	ए. के. सिंह, अवर सचिव	डॉ. पंकज सक्सेना, वैज्ञानिक 'जी'
42	लोक शिकायत (सीपीग्राम)	ए. के. सिंह, अवर सचिव	रामपाल सिंह, उपसचिव

क्र.सं.	विषय	सीपीआईओ का नाम एवं पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	एफएए का नाम और पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती
43	आई एफ डी	गीता राजा, अवर सचिव	कैलाश चंद, उपसचिव
44	ऑडिट	सुनीता साजवान, अवर सचिव	पंकज गुप्ता, उपसचिव
45	बजट से संबंधित सभी मामले	सुनीता साजवान, अवर सचिव	रामपाल सिंह , उप सचिव
46	सूचना का अधिकार (आरटीआई) मामले	मालाराम सोनवाल, उप निदेशक	रामपाल सिंह, उप सचिव
47	नकद अनुभाग	अंजना, अनुभाग अधिकारी एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी	एम. आर. सोनवाल, उप निदेशक
48	पुस्तकालय	सुनीता साजवान, अवर सचिव	समीर कुमार दास, उप सचिव
49	राजभाषा	शीबा जयराज, उप निदेशक	एस.के. शाही, वैज्ञानिक–ई
50	पीएओ; बजट	धर्मेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	अभिजीत रॉय, लेखा नियंत्रक
51	नाइस के सभी प्रशासनिक और वित्तीय मामले	सीमा श्रीवास्तव, अवर सचिव	कुलदीप राणा, वैज्ञानिक–ई
53	माननीय मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का कार्यालय	डी. के. पांडे, अवर सचिव	पंकज गुप्ता, उप सचिव
54	संघ राज्य क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा; नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग, ब्लॉकचेन और डीप लर्निंग जैसे आईटी टूल्स का अध्ययन	संजय प्रकाश भगत, वैज्ञानिक 'सी'	डॉ. ए. के. त्रिपाठी, वैज्ञानिक 'जी'

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 152 08-04-2025 23:58:37

अध्याय 11

भारत और विश्व: अंतरराष्ट्रीय सहयोग

11.1 मंत्रालय का अंतरराष्ट्रीय संबंध (आईआर) प्रभाग अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, भारतीय मिशनों, भारत में स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों, बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं, क्षेत्रीय समूहों और विकास बैंकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में है।

चित्र. 11.1

11.2 संयुक्त गतिविधियों की पहचान, चयन और तैयार करने के लिए संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी), कार्यबल बैठकें और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठकें आयोजित की गई। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन बैठकों और कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। वर्ष 2024 के दौरान आयोजित जेडब्ल्यूजी का विवरण इस प्रकार है:-

1	भारत-श्रीलंका अक्षय ऊर्जा की प्रथम जेडब्ल्यूजी बैठक	11 मार्च, 2024
2	हाइब्रिड मोड में आयोजित इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की बैठक	05 मार्च, 2024
3	वर्चुअल मोड में भारत – अमेरिका-भारत आरईटीएपी की प्रथम जेडब्ल्यूजी बैठक	05 अप्रैल, 2024
4	अमेरिका-भारत सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (एससीईपी) अक्षय ऊर्जा स्तंभ की जेडब्ल्यूजी बैठक	07 मई, 2024
5	वर्चुअल मोड में भारत-जापान अक्षय ऊर्जा की तीसरी जेडब्ल्यूजी बैठक	21 मई, 2024
6	संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) की बैठक, भारत-यूएई ग्रीन हाइड्रोजन समझौता ज्ञापन	21 मई, 2024
7	वर्चुअल मोड में भारत-नाइजीरिया अक्षय ऊर्जा की प्रथम जेडब्ल्यूजी बैठक	19 जुलाई, 2024
8	भारत-फिनलैंड अक्षय ऊर्जा की चौथी जेडब्ल्यूजी बैठक	20 अगस्त, 2024
9	अमेरिका-भारत आरईटीएपी की दूसरी संचालन समिति की बैठक	22 अगस्त, 2024
10	भारत-डेनमार्क की सातवीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक	11 दिसम्बर, 2024
11	वर्चुअल मोड में भारत-स्वीडन की तीसरी संयुक्त कार्य समूह की बैठक	17 दिसम्बर, 2024

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 154 08-04-2025 23:58:37

11.3 मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की है। मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न देशों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू), संयुक्त आशय घोषणा (जेडीआई) पर हस्ताक्षर किए हैं।

चित्र. 11.2

वर्ष 2024 में निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं:-

i. अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश सहयोग पर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट और भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर दिनांक 09 जनवरी, 2024 को हस्ताक्षर किए गए।

ii. अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और गवर्नमेंट ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया के बीच समझौता ज्ञापन पर दिनांक 22 जनवरी, 2024 को हस्ताक्षर किए गए।

iii. अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत-नीदरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन पर दिनांक 12 सितम्बर, 2024 को हस्ताक्षर किए गए।

11.4 वर्ष 2025 के दौरान कुछ प्रमुख द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वार्ताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. अक्षय ऊर्जा के त्वरित विस्तार के लिए ठोस और टिकाऊ समाधान विकसित करने के लिए दिनांक 16 सितम्बर, 2024 को चौथे आरई-इन्वेस्ट में इंडिया-जर्मनी प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जीज वर्ल्डवाइड की शुरुआत की गई। यह मंच निजी क्षेत्र (वित्तीय क्षेत्र और उद्योग दोनों), अंतरराष्ट्रीय संगठनों, विकास बैंकों और द्वि पक्षीय भागीदारों सहित दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय हितधारकों को पूंजी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उन्नत तकनीकी समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए व्यापार के अवसर पैदा करने के लिए एक साथ लाएगा।

ii. भारत-ऑस्ट्रेलिया अक्षय ऊर्जा साझेदारी दिनांक 19 नवम्बर, 2024 को शुरू की गई थी, जो सौर पीवी, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और संबद्ध क्षेत्रों में दो-तरफा निवेश जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग के लिए रूपरेखा और भविष्य के नवीकरणीय कार्यबल के लिए उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

iii. इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप की शुरुआत दिनांक 25 अक्तूबर, 2024 को नई दिल्ली में सातवें अंतर-सरकारी परामर्श (आईजीसी) के दौरान ग्रीन हाइड्रोजन के बाजार रैंप-अप को बढ़ावा देने के लिए की गई। रोडमैप निवेश के अवसरों की पहचान करने और बढ़ावा देने, ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव उत्पादों में वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निजी क्षेत्र के नेटवर्क और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है। यह अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं और साझेदारी के संयुक्त विकास पर भी जोर

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 155 08-04-2025 23:58:37

देता है। इसके अतिरिक्त, रोडमैप प्रमुख परियोजनाओं में निवेश में सहयोग करने के लिए उपकरणों की पहचान करने, विनियमों, मानकों, सुरक्षा प्रक्रियाओं और हरित हाइड्रोजन के लिए स्थिरता मानदंडों पर ज्ञान साझा करने पर केन्द्रित है। इसमें प्रमाणन योजनाओं, विनिर्माण अवसरों की खोज और क्षमता निर्माण पर सहयोग भी शामिल है। सहयोग को और मजबूत करने के लिए रोडमैप मौजूदा ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स को सफल बनाने के लिए इंडो-जर्मन फोरम के तहत एक स्थायी कार्य समूह की स्थापना करता है।

चित्र. 11.3

11.5 अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (इरेना) के साथ जुड़ाव

अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (इरेना) की असेंबली के 14वें सत्र का दो भागों में आयोजन किया गया। 14वीं सभा का भाग-I वस्तुतः दिनांक 15 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री 13वें इरेना विधानसभा अध्यक्ष श्री आर.के. सिंह ने उद्घाटन भाषण दिया और रवांडा को औपचारिक रूप से प्रेसीडेंसी सौंपी। भारत ने सभा के भाग-II में भी भाग लिया, जिसका अबूधाबी में 16-18 अप्रैल, 2024 तक आयोजन किया गया।

चित्र. 11.4

11.6 अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के साथ जुड़ाव

दिनांक 04 नवम्बर, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित आईएसए की वार्षिक सभा के 7वें सत्र में 130 देशों के 450 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत गणराज्य को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्विरोध चुना गया, जबकि फ्रांस गणराज्य को 2 वर्ष की अवधि के लिए आईएसए सभा के सह–अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। आईएसए सभा ने भारत गणराज्य की ओर से महानिदेशक के रूप में नामित श्री आशीष खन्ना का भी आईएसए में 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए चयन किया।

इससे पूर्व, दिनांक 05 सितम्बर, 2024 को आईएसए ने नई दिल्ली में अपने प्रथम 'अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव' का आयोजन किया था। इस आयोजन ने सौर ऊर्जा का उत्सव मनाने के लिए वैश्विक समुदाय को साथ किया। उत्सव का उद्देश्य नीति निर्माताओं, उद्योग प्रमुख, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और जनता को सौर ऊर्जा समाधानों पर चर्चा करने और बढ़ावा देने के लिए एकजुट करना था।

चित्र. 11.5

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 157 08-04-2025 23:58:38

RE- INVEST

अध्याय 12

विशेष आकर्षण: चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशकों की बैठक एवं एक्सपो

12.1 भारत सरकार द्वारा इरेडा और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ साझेदारी में आयोजित अक्षय ऊर्जा वैश्विक निवेशक सम्मेलन और एक्सपो ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डालते हुए देश की अक्षय ऊर्जा संभाव्यता को प्रदर्शित किया और महत्वपूर्ण वैश्विक निवेश आकर्षित किया। इस कार्यक्रम में 50,000 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ 43 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 250 अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति और वक्ता शामिल थे, और इसमें डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदार देशों की भागीदारी रही। आठ भागीदार राज्य, अर्थात् गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 22 अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधी भी साथ-साथ शामिल थे। प्रमुख परिणामों में अक्षय ऊर्जा में निवेश के लिए भारत-जर्मनी प्लेटफॉर्म के लिए एक प्रमुख समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना शामिल था, जिसका उद्देश्य स्थायी समाधान का विकास करना था। प्रदर्शनी में पर्यावरण-कुशल सौर मॉड्यूल, पवन टर्बाइन और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों जैसी उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन किया गया, जबकि 363 कंपनियों ने 816 बी2बी और 110 बी2जी बैठकों में भाग लिया। इस आयोजन ने सोशल मीडिया पर 377.5 मिलियन की प्रभावशाली पहुंच हासिल की, जिसमें प्रचलित हैशटैग ने इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। मुख्य बातों में राज्यों और डेवलपर्स की ओर से पर्याप्त प्रतिबद्धताएं (शपथ पत्र) शामिल थीं, जिसमें गुजरात ने वर्ष 2030 तक 128.60 गीगावॉट क्षमता जोड़ने का संकल्प लिया, और कुल निवेश से 82 लाख नौकरियों के सृजन की उम्मीद है, जिसे वित्तीय संस्थानों से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त है। इस आयोजन ने भारत को वैश्विक अक्षय ऊर्जा प्रयासों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

12.2 कुछ प्रमुख विशेषताएं

- सत्रों की कुल संख्या: 43
- प्रतिनिधि और वक्ता: देश भर से 50,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने पंजीकरण किया, जिनमें 20,000 से अधिक छात्र और शिक्षा जगत के सदस्य शामिल थे। 250 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपस्थित थे, और 250 वक्ता भी मौजूद थे।
- राज्यों के मुख्यमंत्री: गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा के छह मुख्यमंत्री और तेलंगाना से एक उपमुख्यमंत्री
- देशों की भागीदारी: डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया भागीदार देश थे। यूएई, सिंगापुर, भूटान जैसे देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए
- राज्य: आठ भागीदार राज्य थे: गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा छह राज्य सत्र (गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश)।

इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ (यूटी), दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (यूटी), दिल्ली [राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी)], जम्मू और कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), पुडुचेरी (यूटी) जैसे 22 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (साझीदार राज्यों के अलावा) के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे।

हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापनों की संख्या: विश्व भर में अक्षय ऊर्जा में निवेश के लिए भारत-जर्मनी मंच: इसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के शीघ्र विस्तार के लिए ठोस और टिकाऊ समाधान विकसित करना है। यह मंच निजी क्षेत्र (वित्तीय क्षेत्र और उद्योग दोनों), अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विकास बैंकों और द्विपक्षीय भागीदारों सहित दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ लाएगा, ताकि व्यापार के अवसरों का सृजन किया जा सके और पूंजी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा उन्नत तकनीकी समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 160 08-04-2025 23:58:38

12.3 प्रदर्शनी की मुख्य विशेषताएं

मुख्य विवरणः-

ग्लोबल री-इन्वेस्ट प्रदर्शनी 2024 के चौथे संस्करण में अत्याधुनिक टिकाऊ इंजीनियरिंग डिजाइन, प्रौद्योगिकी और नवाचार का प्रदर्शनः

अक्षय विद्युत उत्पादन	हरित ईंधन एवं ऊर्जा भंडारण	जीएचजी उत्सर्जन में कमी और निवल शून्य परामर्श	लागत प्रभावी परिचालन रणनीतियाँ
सौर ऊर्जा उत्पादन संवर्धन एवं परिसंपत्ति अनुकूलन	अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ	रूफटॉप सौर ऊर्जा और स्वायत्त रोबोटिक प्रणालियाँ	सौर आईपीपी/ईपीसी सेवाएं
फ्लेक्सी बायोगैस से बायो-सीएनजी संयंत्र	ऊर्जा दक्षता के लिए ईपीसी समाधान	ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन	

अग्रणी अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स, विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं ने चौथी री-इन्वेस्ट प्रदर्शनी में उन्नत उत्पादों और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया।

पर्यावरण-कुशल पी.वी. मॉड्यूल, सौर मॉड्यूल और सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल	सौर ऊर्जा चालित नवाचारः फूड ट्रक, मॉड्यूलर कियोस्क, बैटरी चालित कुकिंग प्लेट्स
भारत में निर्मित पवन टर्बाइन (छोटे और बड़े पवन टर्बाइन जनरेटर - डबल्यूटीजी)	• डीसी एयर हीटर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कंप्रेसर और फ्रीजर
• उन्नत इलेक्ट्रोलाइजर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली	**फ्रीजर** • हरित ऊर्जा उत्पादः सौर पंप, सौर पेड़, सौर टाइलें और सौर मुखौटे
• ईवी स्कूटर और स्मार्ट सोलर हट्स	• रूफटॉप, ग्राउंड माउंटेड और स्ट्रीट लाइटीन्ग समाधान
• मेम्बरेन-रहित इलेक्ट्रोलाइजर और भारी इंजीनियरिंग उत्पाद	• सौर ईवी चार्जिंग, हाइब्रिड कलेक्टर, ट्रैकर और सामग्री हैंडलिंग उपकरण
• बायोमास और नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) - आधारित गैसीफायर, रोटरी भट्टियां, गैसफायर, और अधिक	

12.4 सोशल मीडिया गतिविधिया

अनुमानित पहुंच	मिलियन पहुंच	जुड़ाव	पोस्ट
377.5 मिलियन	8+ मिलियन	67.4k	500+

#REINVEST2024 और संबोधित हैशटैग एक्स प्लेटफॉर्म पर सभी 3 दिनों तक ट्रेंड करते रहे।

मुख्य वक्ता - माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय उपराष्ट्पति श्री जगदीप धनखड़, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी, श्री भूपेन्द्र पटेल, श्री एन चंद्रबाबू नायडू, डॉ मोहन यादव, श्री भजनलाल शर्मा, श्री श्रीपद वाई नाइक, श्री जी किशन रेड्डी, श्री हिमंत बिस्वा सरमा, मिंट, सीएनबीसी टीवी 18, हिंदुस्तान टाइम्स, डीडी न्यूज, एमआईबी, एएनआई, एबीपी, ऑल इंडिया रेडियो, और कई अन्य।

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 161 08-04-2025 23:58:38

12.5 तीन दिनों का समग्र परिणाम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए रोडमैप तैयार करना था।	अक्षय ऊर्जा के प्रति भारत के बहुमुखी दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया, जिसमें सौर, पवन, पंप भंडारण, हरित हाइड्रोजन और विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया
कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लक्ष्य पर जोर दिया गया	नवीकरणीय पहलों को बढ़ावा देने में नीतिगत सहायता की भूमिका की पहचान की गई
मान्यता प्राप्त प्रगति जो अक्षय ऊर्जा दक्षता और एकीकरण को बढ़ाती है	नवीकरणीय क्षेत्र में निवेश के अवसर प्रदर्शित किये गये
जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य	भारत अंतरराष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों में योगदान देने के लिए तैयार

12.6 B2B, B2G, G2G की कुल संख्या

इसमें भारतीय और वैश्विक व्यापारों का प्रतिनिधित्व करने वाली लगभग 363 कंपनियों ने भाग लिया। 816 B2B (बिजनेस टू बिजनेस) बैठकें और 110 B2G (बिजनेस टू गवर्नमेंट) बैठकें आयोजित की गई।

12.7 मुख्य बातें

राज्यों ने अक्षय ऊर्जा की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया, जिसमें गुजरात अग्रणी रहा और उसने वर्ष 2030 तक 128.60 गीगावाट जोड़ने की प्रतिबद्धता जताई। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने क्रमशः 72.60 गीगावाट और 62.73 गीगावाट की प्रतिबद्धता जताई

इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तपोषण की भी आवश्यकता होगी, इसलिए वित्तीय संस्थान भी आगे आए हैं और 25 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताते हुए, मजबूत समर्थन प्रदर्शित किया है। आरईसी, इरेडा लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक जैसे प्रमुख बैंक और वित्तीय संस्थान इस प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं

अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स, सौर और पवन – दोनों, 570 गीगावाट स्थापित क्षमता जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और विनिर्माताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं ने भी उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रतिज्ञाएं की हैं

32.45 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता, जिससे 82 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

RE
INVEST 2024

RE
INVEST 2024

अध्याय 13

राजभाषा - हिंदी को बढ़ावा

13.1 **प्रस्तावना:** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा तथा भारत सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में कार्मिकों में जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से एमएनआरई में हिन्दी प्रभाग की स्थापना की गई है। इसके कार्य इस प्रकार है:

i. **अनुवाद कार्य:** मंत्रालय के हिंदी अनुभाग द्वारा, मंत्रालय के विभिन्न दस्तावेजों, जिनमें संसद में रखे जाने वाले कागजात जैसे संसदीय प्रश्नोत्तर, संसदीय आश्वासन, स्थायी समितियों और अन्य संसदीय समितियों से संबंधित दस्तावेज, प्राइवेट मेंबर बिल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, बजट संबंधी दस्तावेज, अनुदानों की मांग, वार्षिक रिपोर्ट, अधि सूचनाएं, सामान्य आदेश, विज्ञापन, निविदा, समझौता ज्ञापन/करार ज्ञापन, मंत्रिमंडल नोट, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कार्यालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त विभिन्न वक्तव्य/भाषण और अन्य कागजातों तथा प्रैस विज्ञप्तियों इत्यादि का नियमित रुप से अनुवाद किया जाता है।

ii. भारत सरकार की राजभाषा नीति; राजभाषा अधिनियम, 1963; राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976; सरकार द्वारा हिंदी के प्रयोग के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों/अनुदेशों; राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रति वर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम और माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति की ओर से जारी आदेशों का कार्यान्वयन।

iii. वर्तमान में, हिन्दी प्रभाग वैज्ञानिक-जी (संयुक्त सचिव स्तर) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, जिनकी सहायता के लिए वैज्ञानिक-ई (निदेशक स्तर), उप निदेशक (राजभाषा)/सहायक निदेशक (राजभाषा) हैं। राजभाषा प्रभाग में एक उप निदेशक (राजभाषा), एक सहायक निदेशक (राजभाषा), दो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, दो कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और दो हिन्दी टाइपिस्ट हैं। राजभाषा प्रभाग, मंत्रालय के साथ-साथ अपने प्रशासनिक नियंत्रणाध ीन सभी कार्यालयों/संस्थानों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। यह मंत्रालय में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मंत्रालय में राजभाषा हिन्दी में किए जाने वाले कार्यों में सतत वृद्धि हो रही है और आशा है कि निकट भविष्य में मंत्रालय, सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा।

13.2 वर्ष 2024-25 के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके तहत गठित नियमों के प्रावधानों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए।

13.3 राजभाषा नीति को प्रभावी कार्यान्वयन की दृष्टि से तथा कार्मिकों के लिए अधिकाधिक कार्य हिन्दी भाषा में करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. मंत्रालय में भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजभाषा नीति के प्रावधानों, के अनुसार मंत्रालय में कुछ जांच बिंदु निर्धारित करके अनुपालना के लिए परिचालित किए गए हैं।

ii. मंत्रालय की वेबसाइट को द्विभाषी बनाया गया है और उसे समय-समय पर अद्यतित किया जा रहा है।

iii. मंत्रालय में पुस्तकालय द्वारा हिंदी पुस्तकों की खरीद की जाती है और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं।

iv. नोडल एजेंसियों के पते हिंदी में तैयार किए गए हैं।

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 164 08-04-2025 23:58:39

v. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात, जैसे प्रैस विज्ञप्तियां, निविदा सूचनाएं, नियम, सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, मंत्रिमंडल नोट, संसद प्रश्न तथा संसद के समक्ष रखे जाने वाले अन्य सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए।

vi. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिया जाता है और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का पूर्ण अनुपालन किया गया।

vii. मंत्रालय की वेबसाइट हिन्दी भाषा में खुलती है।

viii. मंत्रालय के ई–ऑफिस में तात्कालिक अनुवाद की सुविधा प्रदान करने हेतु कंठस्थ–टूल को ई-ऑफिस में जोड़ा गया है।

13.4 वर्ष 2024–25 के दौरान मंत्रालय में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनेक प्रयास किए गए। दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 की स्थिति के अनुसार 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ हिन्दी में पत्राचार की प्रतिशतता क्रमश: 74.65%, 90.12% और 82.75% थी। मंत्रालय में ही नहीं बल्कि इसके स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

13.5 मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं। मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों व प्रभागों तथा अन्य संगठनों अर्थात इरेडा, सेकी, नीवे, नाइस और नीबे से प्राप्त तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है। अनुभागों व प्रभागों और अन्य संगठनों को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

13.6 राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही में एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

13.7 हिंदी पखवाड़ा और पुरस्कार वितरण समारोह

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के प्रति जागरुकता लाने और उसके प्रयोग में वृद्धि लाने के लिए मंत्रालय में 14 से 29 सितम्बर, 2024 तक 'हिन्दी पखवाड़ा' मनाया गया। इस दौरान अनेक हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह- पूर्वक से भाग लिया। दिनांक 09 अक्तूबर, 2024 को आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान अपर सचिव, एमएनआरई द्वारा हिन्दी और हिन्दीतर भाषी कुल 57 अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर नकद पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र दिए गए। मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न स्वायत्त संस्थानों और उपक्रमों में भी हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी के प्रचार व प्रसार को प्रभावी एवं व्यापक बनाने के लिए उन्हें आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए।

13.8 हिंदी सलाहकार समिति

मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की पुनर्गठन प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से प्रगति पर है। हिंदी सलाहकार समिति केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य मंत्रालय को सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के संबंध में सलाह देना है।

13.9 नियंत्रणाधीन कार्यालयों का निरीक्षण

राजभाषा को बढ़ावा देने से संबंधित स्थिति का आकलन करने के लिए मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पाँच में से चार कार्यालयों (इरेडा/सेकी/नाइस, नीवे और नीबे) का निरीक्षण किया गया और उनके कार्यालयों को संघ की राजभाषा नीति की अनुपालना के लिए सुधारात्मक उपाय करने के संबंध में सुझाव दिए गए।

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 165 08-04-2025 23:58:39

चित्र. *13.1 :* 9.10.2024 को आयोजित अपार सचिव, एमएनआरई की अध्यक्षता में हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 166 08-04-2025 23:58:39

अनुलग्नक I

स्टाफ क्षमता

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (प्रशासन)

तालिका 1: दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार, एमएनआरई में स्वीकृत और कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

ग्रुप	क	ख	ग	घ
स्वीकृत	135	83	84	302
कार्यरत	88	62	68	218
अनुसूचित जाति	11	12	16	39
अनुसूचित जनजाति	3	3	8	14
अन्य पिछड़ा वर्ग	13	14	13	40
पीडब्ल्यूबीडी	0	2	3	5

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नीवे)

तालिका 2: दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार नीवे में समूहवार स्वीकृत और कार्यरत पद निम्नानुसार हैं:

पदों की संख्या	ग्रुप ''			कुल
	क	ख	ग	
स्वीकृत	18	13	17	48
कार्यरत	13	07	16	36
अनुसूचित जाति	04	02	05	11
अनुसूचित जनजाति	01	–	–	01
अन्य पिछड़ा वर्ग	04	03	11	18
दिव्यांगजन	–	–	–	–

****पदों का वर्गीकरण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं.**11012/10/2016-स्था.ए-III दिनांक 08-12-2017 **के अनुसार है।**

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा)

तालिका 3: दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार इरेडा में कर्मचारी स्टाफ संख्या निम्नानुसार है: –

वर्गीकरण	बोर्ड स्तर	ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप सी	ग्रुप डी	कुल

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 167 08-04-2025 23:58:39

कार्यरत	02	148	04	16	00	170
अनुसूचित जाति	00	14	01	03	00	18
अनुसूचित जनजाति	00	06	00	01	00	07
अन्य पिछड़ा वर्ग	00	27	00	03	00	30
दिव्यांगजन	00	04	00	01	00	05

कुल स्वीकृत संख्या (बोर्ड स्तर से नीचे) ३०५ है।

सरदार स्वर्ण सिंह - राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान (एसएसएस-नीबे)

तालिका 4: दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार एसएसएस-नीबे में ग्रुपवार स्वीकृत और कार्यरत पद निम्नानुसार हैं:

ग्रुप	बोर्ड स्तर	क	ख	ग	घ	कुल
स्वीकृत	1 (उप निदेशक)	20	1	4	0	26
कार्यरत	1 (उप निदेशक)	11	1	4	0	17
अनुसूचित जाति	-	-	-	-	-	-
अनुसूचित जनजाति	-	-	-	-	-	-
अन्य पिछड़ा वर्ग	0	2	0	0	0	2
दिव्यांगजन	-	-	-	-	-	-

नोट- रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस)

तालिका 5: दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार नाइस में समूहवार स्वीकृत और कार्यरत पद निम्नानुसार हैं:

क्रम सं	पद का नाम	स्तर	स्वीकृत पदों की संख्या			भरा हुआ पोस्ट		रिक्त पदों की संख्या		
			तकनीकी	प्रशा.	कुल	तकनीकी	प्रशा	तकनीकी	प्रशा.	कु
1.	महानिदेशक	14	01	00	01	01	00	00	00	00
2.	उप महानिदेशक	13d	03	00	03	03	00	00	00	00
3.	निदेशक	12	02	01	03	02	01	00	00	00
4.	उप निदेशक	11	06	02	08	06	02	00	00	00
5.	प्रशासनिक अधिकारी	11	-	01	01	00	01	00	00	00
6.	सहायक निदेशक	10	07	02	09	07	02	00	00	00
7.	कार्यालय सचिव	9	-	01	01	00	00	00	01	01
8.	कार्यालय सचिव-I	8		03	03	00	00	00	03	03
9.	कार्यकारी अधिकारी	8	04	-	04	00	00	04	00	04
10.	कार्यकारी सहायक-I	7	08	-	08	03	00	05	-	05

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 168 08-04-2025 23:58:39

क्रम सं	पद का नाम	स्तर	स्वीकृत पदों की संख्या			भरा हुआ पोस्ट		रिक्त पदों की संख्या		
			तकनीकी	प्रशा.	कुल	तकनीकी	प्रशा	तकनीकी	प्रशा.	कु
	कुल		31	10	41	22	06	09	04	13

भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी)

तालिका 6: दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार सेकी में ग्रुपवार स्वीकृत और कार्यरत पद

ग्रुप	क	ख	ग	घ	कुल
स्वीकृत	275	42	गैर वैकल्पिक		317
कार्यरत	129	19			148
अनुसूचित जाति	15	1			16
अनुसूचित जनजाति	4	1			5
अन्य पिछड़ा वर्ग	25	8			33
दिव्यांगजन	2	1			3

वेतन एवं लेखा कार्यालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

तालिका 7: दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार वेतन एवं लेखा कार्यालय, एमएनआरई में ग्रुपवार स्वीकृत और कार्यरत पदों की स्थिति है।

समूह	क	ख	ग	कुल
स्वीकृत	04	04	14	22
कार्यरत	04	04	11	18
अनुसूचित जाति	01	01	01	03
अनुसूचित जनजाति	00	00	00	00
अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00	02	02
दिव्यांगजन	00	00	00	00

अनुलग्नक II

लेखा परीक्षण पैरा

मंत्रालय में लंबित 8 सीएजी पैरा का विवरण और स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.स.	वर्ष	प्रतिवेदन संख्या.	अध्याय सं.	पैरा नं.	विषय	अनुवर्ती कार्रवाई
1,2,3			3	3.2.1 बी चित्र 3.1 क्रम संख्या 1,2,3	गारंटी शुल्क की देरी से प्राप्ति के लिए लगाए गए जुर्माने की राशि का न मिलना।	एटीएन प्रस्तुत की जा चुकी है।
4				4.16 चित्र 4.17	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र।	एटीएन प्रस्तुत की जा चुकी है।
5	2023	2023 की 21वीं	4	4.6 अनुलग्नक 4.7 क्रम संख्या 38	वित्त वर्ष के अंतिम दिन पर बचत की धनराशि का गैर-अभ्यर्पण और अभ्यर्पण।	एटीएन प्रस्तुत की जा चुकी है।
6				4.2.2.2 अनुलग्नक 4.3बी क्रम संख्या 99 से 101	लघु/उपशीर्ष स्तर पर 100 करोड़ या उससे अधिक की अन्य महत्वपूर्ण बचत।	एटीएन प्रस्तुत की जा चुकी है।
7				4.2.2 अनुलग्नक 4.2 क्रम संख्या 40	बचत विश्लेषण – खंडवार।	एटीएन प्रस्तुत की जा चुकी है।
8		2023 की 24वीं	6	6.1	13 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय।	एटीएन प्रस्तुत की जा चुकी है।

मंत्रालय में लंबित 3 पीएसी पैरा के विवरण और स्थिति निम्नानुसार है

क्रम सं.	लोक सभा सं.	प्रतिवेदन संख्या	पैरा सं.	विषय	अनुवर्ती कार्रवाई
1, 2, 3	17	112	5, 8 और 11	सौर ताप विद्युत संयंत्र का उपयोग न होना	एटीआर प्रस्तुत की जा चुकी है।

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 170 08-04-2025 23:58:39

अनुलग्नक III

राज्यों और स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान सहायता

तालिका 1: दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी निधियां।

क्रम सं.	स्वीकृति सं.	एजेंसी का नाम	स्वीकृति तिथि	राशि (रु. में)
1.	342-11/5/2023-एचआरडी	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम	07.02.2024	38,75,401/-
2.	342-11/5/2021-एचआरडी	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम	09.02.2024	9,13,00,000/-
3.	342-11/5/2021-एचआरडी	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम	29.03.2024	1,94,65,071/-
4.	342-11/2/2024-एचआरडी	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम	12.07.2024	3,86,00,000/-
5.	342-11/1/2022-एचआरडी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	15.07.2024	2,00,00,000/-
6.	342-11/5/2021-एचआरडी	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम	15.07.2024	3,00,00,000/-
7.	342-11/6/2020-एचआरडी	राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	25.07.2024	2,00,00,000/-
8.	342-11/5/2021-एचआरडी	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम	07.10.2024	5,00,00,000/-
9.	342-14/2/2024-एचआरडी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	03.06.2024	24,88,309/-
10.	342-14/4/2024-एचआरडी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	26.09.2024	28,26,468/-
11.	342-14/3/2024-एचआरडी	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय	08.10.2024	22,25,480/-
12.	342-14/1/2024-एचआरडी	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन	20.11.2024	24,59,743/-
13.	342-11/5/2021-एचआरडी	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम	03.12.2024	5,00,00,000/-

दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में राज्य पीआईए को 50 लाख से अधिक का निर्गत अनुदान

क्रम. सं	स्वीकृति सं.	परियोजना/संगठन का नाम	राज्य	जारी की गई निधि	
				स्वीकृति की तिथि	राशि (लाख रुपए में)
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-I					
1	1/7/2015-ईएफएम-भाग(1)	तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टेनट्रांसको)	तमिलनाडु	17.12.2024	1046.78
2	1/7/2015- ईएफएम	गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड(जीईटीसीईओ)	गुजरात	19.12.2024	1777.00
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-II					

क्रम. सं	स्वीकृति सं.	परियोजना/संगठन का नाम	राज्य	जारी की गई निधि	
				स्वीकृति की तिथि	राशि (लाख रुपए में)
3	367-12/2/2024-जीईसी	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल)	कर्नाटक	18.03.2024	6666.61
4	367-12/2/2023-जीईसी (भाग-1)	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल)	उत्तरप्रदेश	26.03.2024	7815.06*
5	367-12/2/2023-जीईसी (भाग-1)	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल)	उत्तरप्रदेश	12.08.2024	15666.02
6	367-12/2/2023-जीईसी (भाग-1)	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल)	उत्तरप्रदेश	20.09.2024	1462.63
7	367-12/2/2023-जीईसी (भाग-1)	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल)	उत्तरप्रदेश	31.12.2024	12164.40
8	367-12/2/2024-जीईसी	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल)	कर्नाटक	31.12.2024	2465.00
	कुल				49063.5

तथापि, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 7815.06 लाख रुपये की धनराशि यूपीपीटीसीएल से भारत की समेकित निधि में अव्ययित शेष के रूप में वापस कर दी गई है।

तालिका 3: भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी) / भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) द्वारा सौर पार्क योजना के अंतर्गत विभिन्न पार्क डेवलपर्स को दिनांक 01-01-2024 से दिनांक 31-12-2024 तक जारी सीएफए।

क्र. सं.	राज्य	सौर पार्क	सौर पार्क योजना के अंतर्गत जारी सीएफए (भारतीय रुपये में)
1	छत्तीसगढ	100 - राजनांदगांव सौर पार्क	5,00,00,000
2	मध्य प्रदेश	630 - बरेठी सौर पार्क	25,45,00,000
3	मिजोरम	20 - वांकल सौर पार्क	2,24,00,000
4	राजस्थान	2000 - आरवीयूएन सौर पार्क	72,64,62,120
5	उत्तरप्रदेश	600 - झांसी सौर पार्क	48,00,00,000
6	उत्तरप्रदेश	365 - यूपी सोलर पार्क	11,56,57,940
7	उत्तरप्रदेश	1200 - जालौन सौर पार्क	47,81,76,000
		कुल	212,71,96,060

तालिका 4: दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक पीएम कुसुम के अंतर्गत 50 लाख रुपये से अधिक जारी की गई निधियां

क्र. सं.	स्वीकृति सं.	राज्य	जारी निधियां	
			दिनांक	राशि (रु.
1	32/698/2022- एसपीवी प्रभाग	झारखंड	29-02-2024	23600000
2	32/698/2022- एसपीवी प्रभाग	हरियाणा	29-02-2024	1100500000
3	32/2/2024- एसपीवी डिवीजन	गुजरात	08-03-2024	7200000
4	32/75/2023- एसपीवी प्रभाग	गुजरात	08-03-2024	176800000
5	32/12/2020-एसपीवी प्रभाग	उत्तरप्रदेश	09-03-2024	60806509
6	32/12/2021- एसपीवी प्रभाग	महाराष्ट्र	11-03-2024	225500000
7	32/694/2022- एसपीवी प्रभाग	हरियाणा	18-03-2024	826150000
8	32/5/2023- एसपीवी प्रभाग	मणिपुर	18-03-2024	1668000
9	32/07/2023- एसपीवी प्रभाग	अरुणाचल प्रदेश	18-03-2024	6040000
10	32/7/2024- एसपीवी प्रभाग	अरुणाचल प्रदेश	18-03-2024	9060000
11	32/8/2024- एसपीवी प्रभाग	हरियाणा	27-03-2024	312100000
12	32/3/2024- एसपीवी प्रभाग	तमिलनाडु	27-03-2024	25920000
13	32/6/2024- एसपीवी प्रभाग	महाराष्ट्र	27-03-2024	739900000
14	32/6/2024- एसपीवी प्रभाग	महाराष्ट्र	27-03-2024	740439000
15	32/8/2024- एसपीवी प्रभाग	हरियाणा	27-03-2024	5400000
16	32/6/2024-एसपीवी प्रभाग	महाराष्ट्र	29-04-2024	3251161000
17	32/43/2024- एसपीवी प्रभाग	महाराष्ट्र	11-05-2024	449200000
18	32/12/2021 -एसपीवी प्रभाग	महाराष्ट्र	09-06-2024	920050363
19	32/41/2024-एसपीवी प्रभाग	उत्तराखंड	11-06-2024	115380000
20	32/3/2024- एसपीवी प्रभाग	तमिलनाडु	11-06-2024	32700000
21	32/630/2022-एसपीवी प्रभाग	उत्तराखंड	27-06-2024	18508929
22	32/8/2024- एसपीवी प्रभाग	हरियाणा	11-07-2024	438800000
23	32/694/2022-एसपीवी प्रभाग	हरियाणा	26-07-2024	442300000
24	32/13/2020-एसपीवी प्रभाग	झारखंड	26-07-2024	131526795
25	32/7/2020- एसपीवी प्रभाग	राजस्थान	26-07-2024	237956230
26	32/11/2020-एसपीवी प्रभाग	हरियाणा	26-07-2024	578399991
27	32/8/2024-एसपीवी प्रभाग	हरियाणा	26-07-2024	12697948
28	32/61/2023-एसपीवी प्रभाग	उत्तरप्रदेश	05-08-2024	317500000

क्र. सं.	स्वीकृति सं.	राज्य	जारी निधियां	
			दिनांक	राशि (रु.
29	32/3/2024- एसपीवी प्रभाग	तमिलनाडु	05-08-2024	6080000
30	32/634/2022-एसपीवी प्रभाग	उत्तरप्रदेश	10-08-2024	232582078
31	32/6/2024- एसपीवी प्रभाग	महाराष्ट्र	08-09-2024	1480339000
32	32/517/2022-एसपीवी प्रभाग	पंजाब	13-09-2024	20700000
33	32/22/2020-एसपीवी प्रभाग	पंजाब	13-09-2024	110172949
34	32/4/2024-एसपीवी प्रभाग	उत्तराखंड	13-09-2024	13800000
35	32/31/2024-एसपीवी प्रभाग	कर्नाटक	21-09-2024	812500000
36	32/29/2024-एसपीवी प्रभाग	केरल	23-09-2024	712992
37	32/264/2022-एसपीवी प्रभाग	राजस्थान	27-09-2024	243637266
38	32/698/2022-एसपीवी प्रभाग	झारखंड	22-10-2024	92510172
39	32/60/2023-एसपीवी प्रभाग	उत्तरप्रदेश	24-10-2024	18800000
40	32/25/2024- एसपीवी प्रभाग	हिमाचल प्रदेश	24-10-2024	31324000
41	32/35/2024- एसपीवी प्रभाग	उत्तराखंड	24-10-2024	93200000
42	32/15/2024- एसपीवी प्रभाग	उत्तरप्रदेश	24-10-2024	36200000
43	32/7/2023- एसपीवी प्रभाग	नागालैंड	28-10-2024	1642384
44	32/8/2020-एसपीवी प्रभाग	तमिलनाडु	28-10-2024	1185450
45	32/694/2022-एसपीवी प्रभाग	हरियाणा	11-11-2024	511800000
46	32/36/2024- एसपीवी प्रभाग	गोवा	21-11-2024	4300000
47	32/6/2024- एसपीवी प्रभाग	महाराष्ट्र	25-11-2024	3495800000
48	32/18/2024-एसपीवी प्रभाग	झारखंड	08-12-2024	272200000
50	32/17/2024-एसपीवी प्रभाग	महाराष्ट्र	08-12-2024	1766600000
51	32/62/2023-एसपीवी प्रभाग	राजस्थान	08-12-2024	2318550000
52	32/74/2023-एसपीवी प्रभाग	गुजरात	09-12-2024	51455057
53	32/61/2023-एसपीवी प्रभाग	उत्तरप्रदेश	11-12-2024	562000000
54	32/75/2023 एसपीवी प्रभाग	गुजरात	24-12-2024	179200000
55	32/692/2022-एसपीवी प्रभाग	गुजरात	24-12-2024	76008798
56	32/45/2024-एसपीवी प्रभाग	गुजरात	24-12-2024	10900000
57	32/17/2024- एसपीवी प्रभाग	महाराष्ट्र	24-12-2024	1057800000
58	32/72/2023-एसपीवी प्रभाग	गुजरात	24-12-2024	12575000
59	32/8/2024- एसपीवी प्रभाग	हरियाणा	24-12-2024	474400000

क्र. सं.	स्वीकृति सं.	राज्य	जारी निधियां	
			दिनांक	राशि (रु.
60	32/13/2024-एसपीवी प्रभाग	मिजोरम	25-12-2024	25700000
61	32/39/2024- एसपीवी प्रभाग	ओडिशा	26-12-2024	40880000
62	32/5/2023- एसपीवी प्रभाग	मणिपुर	26-12-2024	1720411
63	32/692/2022-एसपीवी प्रभाग	गुजरात	27-12-2024	1525553
64	32/633/2022- एसपीवी प्रभाग	जम्मू और कश्मीर	31-12-2024	129000000

तालिका 5: दिनांक 1.1.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक (ऑफ-ग्रिड सौर प्रभाग) के अंतर्गत 50 लाख रुपये से अधिक जारी निधियाँ।

क्र. सं.	स्वीकृति सं.		राज्य	जारी निधियां	
				दिनांक	राशि (रु.
1	32/2/2019-एसपीवी डिवीजन	जोरम ऊर्जा विकास एजेंसी	मिजोरम	18.03.2024	2,30,33,168
2	32/2/2019-एसपीवी डिवीजन	जोरम ऊर्जा विकास एजेंसी	मिजोरम	18.03.2024	4,60,00,000
3	32/60/2018-एसपीवी डिवीजन-भाग(4)	हिमाचल प्रदेश सरकार ऊर्जा विकास एजेंसी	हिमाचल प्रदेश	18.03.2024	5,00,00,000
4	32/93/2021-एसपीवी डिवीजन	बीएसएफ	सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जम्मू और कश्मीर फ्रंटियर पर अग्रिम रक्षा स्थान (एफडीएल)	11.10.2024	1,83,04,825
5	32/32/2024-एसपीवी डिवीजन	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	झारखंड	17.10.2024	3,56,90,000
6	32/93/2021-एसपीवी डिवीजन	बीएसएफ	सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जम्मू और कश्मीर फ्रंटियर पर अग्रिम रक्षा स्थान (एफडीएल)	16.12.2024	1,58,25,000
7	32/60/2018 - एसपीवी डिवीजन-भाग (2)	विद्युत विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन	अंडमान और निकोबार	20.12.2024	1,75,09,744

दिनांक 26.06.2023 को राशि जारी की गई थी। तथापि, राशि का उपयोग नहीं किया गया था और प्रक्रिया के अनुसार इसे वापस कर पुनः जारी किया गया।

तालिका 6. दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक राज्यवार व्यय

क्र.सं.	राज्य	कार्यक्रम की पुरानी देनदारी	पीएमएसजीएमबीवाई के अंतर्गत उपभोक्ता को सीएफए	कुल राशि
1	अंडमान और निकोबार	–	85,800	85,800
2	आंध्र प्रदेश	102,939,003	396,609,258	499,548,261
3	अरुणाचल प्रदेश	–		–
4	असम	–	226,094,415	226,094,415
5	बिहार	91,959,970	139,923,720	231,883,690
6	चंडीगढ़	37,849,635	6,662,640	44,512,275
7	छत्तीसगढ	–	36,825,570	36,825,570
8	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	–	2,106,000	2,106,000
9	गोवा	96,872,781	17,506,800	114,379,581
10	गुजरात	10,593,449,591	16,492,063,968	27,085,513,559
11	हरियाणा	796,885,301	655,438,560	1,452,323,861
12	हिमाचल प्रदेश	16,681,445	31,161,207	47,842,652
13	जम्मू और कश्मीर	489,201,187	26,015,715	515,216,902
14	झारखंड	9,578,082	3,916,800	13,494,882
15	कर्नाटक	313,700,791	281,230,944	594,931,735
16	केरल	2,255,008,579	3,544,008,666	5,799,017,245
17	लद्दाख	–	11,566,764	11,566,764
18	लक्षद्वीप	–	9,094,800	9,094,800
19	मध्यप्रदेश	375,351,570	1,348,849,320	1,724,200,890
20	महाराष्ट्र	1,723,566,056	6,021,703,890	7,745,269,946
21	मणिपुर	8,688,800	5,076,324	13,765,124
22	मेघालय	–	656,568	656,568
23	मिजोरम	463,494	3,927,462	4,390,956
24	नगालैंड	–	463,650	463,650
25	दिल्ली	–	52,201,290	52,201,290
26	ओडिशा	48,106,775	83,137,230	131,244,005
27	पुदुचेरी	–	30,255,840	30,255,840
28	पंजाब	204,859,162	217,540,650	422,399,812

29	राजस्थान	631,752,702	1,425,395,574	2,057,148,276
30	सिक्किम	–		–
31	तमिलनाडु	–	924,683,958	924,683,958
32	तेलंगाना	169,888,849	346,854,570	516,743,419
33	त्रिपुरा	–	4,225,914	4,225,914
34	उत्तराखंड	96,917,456	750,325,892	847,243,348
35	उत्तरप्रदेश	228,575,703	3,645,147,018	3,873,722,721
36	पश्चिम बंगाल	–		–
उप-योग (क)	18,292,296,932	36,740,756,777	55,033,053,709	
37	सेकी -राष्ट्रीय पोर्टल	2,707,785,538		2,707,785,538
38	उत्तर रेलवे/आईपीजीसीएल/ डीएमआरसी और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	170,579,017		170,579,017
39	आरईसी-पीएमएसजीएमबीआई अन्य घटक	–	1,240,180,156	1,240,180,156
उप-योग (ख)	2,878,364,555	1,240,180,156	4,118,544,711	
कुल (क)+(ख)		21,170,661,487	37,980,936,933	59,151,598,420

तालिका 7: दिनांक 01.01.2024 **से दिनांक** 31.12.2024 **तक भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (सेकी) को** 750 **मेगावाट वीजीएफ योजना (चरण- II बैच- III) के अंतर्गत जारी निधियां**

क्रम सं.	स्वीकृति संख्या	एजेंसी का नाम	स्वीकृति की तिथि	राशि रु. (लाख में)
3	32/7/2017-सौर ऊर्जा समूह	सेकी	18.03.2024	₹ 11,28,225.00
4	एफ. सं. 32/7/2017-सौर ऊर्जा समूह दिनांक	सेकी	18/04/2024	₹ 41,21,775
5	एफ. सं. 32/7/2017-सौर ऊर्जा समूह दिनांक (एसटी-घटक)	सेकी	04.10.2024	₹ 30,68,000/
6	एफ. सं. 32/7/2017-सौर ऊर्जा समूह दिनांक (एससी-घटक)	सेकी	04.10.2024	₹ 14,01,920
7	एफ. सं. 32/7/2017-सौर ऊर्जा समूह दिनांक (सामान्य-घटक)	सेकी	04.10.2024	₹ 1,63,30,080

तालिका 8: 2000 मेगावाट वीजीएफ योजना (चरण-II बैच-III) के अंतर्गत भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) को दिनांक 01-01-2024 से दिनांक 31-12-2024 तक जारी निधियां

एसआई सं.	स्वीकृति संख्या	एजेंसी का नाम	स्वीकृति तिथि	राशि रु. (लाख में)
6	283/70/2017-ग्रिड सोलर	एसईसीआई	18.03.2024	₹ 6,77,55,102.00
7	283/70/2017-ग्रिड सोलर	एसईसीआई	28.05.2024	₹ 45,01,80,366
8	283/70/2017-ग्रिड सोलर (ST-Com)	एसईसीआई	02.12.2024	₹ 87,82,236.00
9	283/70/2017-ग्रिड सोलर (SC-COM)	एसईसीआई	02.12.2024	₹ 2,16,71,275
10	283/70/2017-ग्रिड सोलर (जनरल-कॉम)	एसईसीआई	02.12.2024	₹ 9,59,09,609.00

तालिका ९: दिनांक 01-01-2024 से दिनांक 31-12-2024 तक भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) को डेमो जीबीआई योजना के अंतर्गत जारी निधियां

एसआई सं.	स्वीकृति संख्या	एजेंसी का नाम	स्वीकृति तिथि	राशि रु. (लाख में)
2	283/61/2018-ग्रिड सोलर	इरेडा	12.11.2024	₹ 36,36,402.00
3	283/62/2018-ग्रिड सोलर	इरेडा	12.12.2024	₹28,44,957.00

तालिका 10: दिनांक 01-01-2024 से दिनांक 31-12-2024 तक भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (सेकी) को आरपीएसएसजीपी योजना के अंतर्गत जारी निधियां

एसआई सं.	स्वीकृति संख्या	एजेंसी का नाम	स्वीकृति तिथि	राशि रु. (लाख में)
3	32/6/2017-सौर ऊर्जा समूह	इरेडा	05.02.2024	₹ 28,19,37,148.00
4	32/6/2017-सौर ऊर्जा समूह	इरेडा	12.03.2024	₹ 1,17,57,542.00
5	32/6/2017-सौर ऊर्जा समूह(ST-COM)	इरेडा	03.10.2024	₹ 9,08,52,073
6	32/6/2017-सौर ऊर्जा समूह(SC-COM)	इरेडा	03.10.2024	₹ 13,06,48,945
7	32/6/2017-सौर ऊर्जा समूह(GEN-COM)	इरेडा	03.10.2024	₹ 58,43,71,657

तालिका 11: दिनांक 01-01-2024 से दिनांक 31-12-2024 तक भारत सरकार के पूर्ण सेवा बांड पर ब्याज के भुगतान के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) को जारी निधियां

एसआई सं.	स्वीकृति संख्या	एजेंसी का नाम	स्वीकृति तिथि	राशि रु. (लाख में)
1.	340-12/2/2018-आईआरईडीए	इरेडा	01-02-2024	₹ 22,27,01,305
2.	340-12/2/2018-आईआरईडीए	इरेडा	15-02-2024	₹ 8,42,87,123
3.	340-12/2/2018-आईआरईडीए	इरेडा	27-02-2024	₹ 31,61,87,705

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 178 08-04-2025 23:58:40

4.	340-12/2/2018-आईआरईडीए	इरेडा	25-07-2024	₹ 21,90,06,667
5.	340-12/2/2018-आईआरईडीए	इरेडा	13-08-2024	₹ 8,31,43,169
6.	340-12/2/2018-आईआरईडीए	इरेडा	28-08-2024	₹ 32,05,38,082

तालिका 12: निजी, स्वैच्छिक संगठनों और राज्य पीआईए को वर्ष 2023-24 (दिनांक 01-01-2024 से दिनांक 31-12-2024 तक) के दौरान 50-00 लाख रुपये से अधिक का अनुदान प्राप्त हुआ।

क्रम सं.	स्वीकृति सं.	परियोजना	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संगठन/एजेंसी	जारी निधियां		टिप्पणी
					तारीख	राशि (लाख रुपए में	
1	285/14/2017 -एसएचपी	मिजोरम सरकार के विद्युत एवं बिजली विभाग द्वारा मिजोरम के चम्फाई जिले में कावलबेम एसएचपी (2◦2 –) परियोजना की स्थापना	मिजोरम	ऊर्जा एवं विद्युत विभाग, मिजोरम	30.01.2024	200.00	सीएफए की अंतिम किस्त जारी
2	286/41/2017 -एसएचपी	केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) द्वारा केरल के कोझिकोड जिले में चथनकोट्टुनाडा एसएचपी (6 –) परियोजना की स्थापना	केरल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी)	22.04.2024	337.50	सब्सिडी की अंतिम किस्त (दूसरी, तीसरी और चौथी किश्त) को एकसाथ मिलकर जारी करना
3	286/3/2017 -एसएचपी	केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) द्वारा केरल के कोझिकोड जिले में पेरुवन्नामुझी एसएचपी (6 –) परियोजना की स्थापना	केरल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी)	21.06.2024	625.00	सब्सिडी की अंतिम किस्त का हिस्सा जारी करना
4	286/3/2017 - एसएचपी (2)	केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) द्वारा केरल के कोझिकोड जिले में पेरुवन्नामुझी एसएचपी (6 –) परियोजना की स्थापना	केरल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी)	21.06.2024	625.00	सब्सिडी की अंतिम किस्त का हिस्सा जारी करना

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 179 08-04-2025 23:58:40

क्रम सं.	स्वीकृति सं.	परियोजना	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संगठन/एजेंसी	जारी निधियां		टिप्पणी
					तारीख	राशि (लाख रुपए में	
5	286/3/2017 -एसएचपी	विद्युत बोर्ड (केएसईबी) द्वारा केरल के कोझिकोड जिले में पेरुवन्नामुझी एसएचपी (6 –) परियोजना की स्थापना	केरल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी)	25.09.2024	250.00	सब्सिडी की अंतिम किस्त का शेष हिस्सा जारी करना
6	286/2/2022 -एसएचपी	आंध्र प्रदेश ट्राइबल पावर कंपनी (एपीट्रिपको) द्वारा आंध्रप्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के पिंजरीकोंडा गांव में पिंजरीकोंडा एसएचपी (1.2 –) परियोजना की स्थापना	आंध्रप्रदेश	आंध्र प्रदेश ट्राइबल पावर कंपनी (एपीट्रिपको)	01-11-2024	170.50	तीसरी और चौथी किश्त के लिए सब्सिडी जारी करना
7	286/174/2017 -एसएचपी	आंध्र प्रदेश ट्राइबल पावर कंपनी (एपीट्रिपको) द्वारा आंध्रप्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के वेटामामिडी गांव में वेटामामिडी एसएचपी (1.2 –) परियोजना की स्थापना	आंध्रप्रदेश	आंध्र प्रदेश ट्राइबल पावर कंपनी (एपीट्रिपको)	01-11-2024	77-50	सब्सिडी की चौथी और अंतिम किस्त जारी करना
8	286/32/2017 -एसएचपी	मेघालय पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईपीजीसीएल) द्व ारा मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में गनोल एसएचपी (3°7.5 –) परियोजना की स्थापना	मेघालय	मेघालय पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईपीजीसीएल)	08-11-2024	200-00	चौथी और अंतिम किस्त का विमोचन
9	286/1/2017 -एसएचपी	केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) द्वारा केरल के इडुक्की जिले में अपर कल्लर एसएचपी (2 –) परियोजना की स्थापना	केरल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी)	02-12-2024	315-00	सब्सिडी की अंतिम (तीसरी और चौथी दोनों मिलाकर) किस्त जारी करना

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 180 08-04-2025 23:58:40

तालिका 13: दिनांक 01-01-2024 से दिनांक 31-12-2024 की अवधि के दौरान सीपीएसयू योजना चरण II के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी निधियां

क्रम सं.	स्वीकृति आदेश	एजेंसी का नाम	स्वीकृति की तिथि	राशि (रु.)
1	302/4/2017-ग्रिड सोलर	सेकी	22.03.2024	4,65,61,101
2	283/15/2023-ग्रिड सोलर	सेकी /इरेडा	22.03.2024	21,70,40,169
3	302/4/2017-ग्रिड सोलर	सेकी	27.05.2024	16,85,68,899
4	283/15/2023-ग्रिड सोलर	सेकी /इरेडा	28.05.2024	48,35,19,515
5	283/15/2023-ग्रिड सोलर (i)	सेकी /इरेडा	04.10.2024	51,99,54,781
6	283/15/2023-ग्रिड सोलर (ii)	सेकी /इरेडा	04.10.2024	71,17,71,494
7	283/15/2023-ग्रिड सोलर (iii)	सेकी /इरेडा	04.10.2024	373,74,97,965

तालिका 14 : दिनांक 01-01-2024 से दिनांक 31-12-2024 तक बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी निधियां

क्रम सं	कार्यान्वयन एजेंसी / राज्य	स्वीकृति संख्या	दिनांक	एमएनआरई द्वारा निर्गत (रु.
1.	ग्रामीण विकास विभाग, सिलवासा दादर और नगर हवेली	253/1/2024-बायोगैस	02.02.2024	574000
2.	उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा, देहरादून (यूरेडा)	253/35/2023-बायोगैस	07.02.2024	2064500
3.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, कोहिमा, नागालैंड	253/2/2024-बायोगैस	08.02.2024	1320000
4.	ग्रामीण विकास विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र	253/123/2017-बायोगैस	21.02.2024	23566147
5.	त्रिपुरा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, अगरतला, त्रिपुरा	253/04/2024-बायोगैस	19.02.2024	5331038
6.	अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	253/3/2024-बायोगैस	06.03.2024	880000
7.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर (एमपीयूएटी), राजस्थान	256/1/2022-बायोगैस	26.03.2024	1069792
8.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र, केआईआईटी भुवनेश्वर	256/1/2022-बायोगैस	26.03.2024	1900000
9.	पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए), चंडीगढ़	253/8/2024-बायोगैस	26.03.2024	12139150
10.	ग्रामीण विकास विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र	253/22/2017-बायोगैस	28.03.2024	35618688
11.	एमपीएसएआईडीसी, भोपाल, मध्यप्रदेश	253/7/2023-बायोगैस	29.03.2024	1050000
12.	एमपीएसएआईडीसी, भोपाल, मध्यप्रदेश	253/7/2023-बायोगैस	29.03.2024	3020000

क्रम सं	कार्यान्वयन एजेंसी / राज्य	स्वीकृति संख्या	दिनांक	एमएनआरई द्वारा निर्गत (रु.
13.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र एमपीयूएटी, उदयपुर राजस्थान	253/19/2023-बायोगैस	23.032024	2000000
14.	कृषि निदेशालय, तिरुवनंतपुरम, केरल	253/26/2023-बायोगैस	26.03.2024	5175000
15.	उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, उत्तर प्रदेश	343/19/2020-बायोगैस	20.03.2024	2800000
16.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र -यूएएस बेंगलुरु	343/1/2023-बायोगैस	18.03.2024	56500000
17.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र यूएएस बंगलुरु	343/2023-बायोगैस	18.03.2024	1700000
18.	उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, उत्तर प्रदेश	343/15/2020-बायोगैस	27.03.2024	3020000
19.	ओडिशा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (ओआरईडीए) भुवनेश्वर	253/12/2023-बायोगैस	08.01.2024	46000
20.	उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा (यूरेडा) देहरादून	253/36/2023-बायोगैस	08.01.2024	325000
21.	ग्रामीण विकास विभाग, सिलवासा दादर और नगर हवेली	253/1/2024-बायोगैस	02.02.2024	287000
22.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, कोहिमा, नागालैंड	253/2/2024-बायोगैस	08.02.2024	440000
23.	ओडिशा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, भुवनेश्वर	253/38/2023-बायोगैस	12.02.2024	31000
24.	त्रिपुरा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	253/4/2024-बायोगैस	19.02.2024	2763000
25.	त्रिपुरा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	253/4/2024-बायोगैस	14.03.2024	723332
26.	अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	253/3/2024-बायोगैस	06.03.2024	660000
27.	पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए), चंडीगढ़	253/7/2024-बायोगैस	19.03.2024	64500
28.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र, एमपीयूएटी, उदयपुर राजस्थान	253/19/2023-बायोगैस	23.03.2024	1000000
29.	कृषि निदेशालय, तिरुवनंतपुरम, केरल	253/26/2023-बायोगैस	26.03.2024	242000
30.	ग्रामीण विकास विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र	253/120/2017-बायोगैस	13.03.2024	4029350
31.	एमपीएसएआईडीसी, भोपाल, मध्य प्रदेश	253/7/2023-बायोगैस	29.03.2024	2376000
32.	ओडिशा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, भुवनेश्वर	253/12/2023-बायोगैस	08.01.2024	31000

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 182 08-04-2025 23:58:40

क्रम सं	कार्यान्वयन एजेंसी / राज्य	स्वीकृति संख्या	दिनांक	एमएनआरई द्वारा निर्गत (रु.
33.	ग्रामीण विकास विभाग, सिलवासा दादर और नगर हवेली	253/1/2024–बायोगैस	02.02.2024	287000
34.	ओडिशा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, भुवनेश्वर	253/38/2023–बायोगैस	12.02.2024	31000
35.	ग्रामीण विकास विभाग, महाराष्ट्र	253/123/2017–बायोगैस	21.02.2024	6475381
36.	त्रिपुरा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, अगरतला	253/4/2024–बायोगैस	19.02.2024	957000
37.	अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	253/3/2024–बायोगैस	06.03.2024	220000
38.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, एमपीयूएटी, उदयपुर	253/19/2023–बायोगैस	23.03.2024	1200000
39.	ग्रामीण विकास विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र	253/22/2017–बायोगैस	28.03.2024	1855519
40.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र-टीएनएयू कोयंबटूर, तमिलनाडु	343/12/2019–बायोगैस	26.03.2024	2450000
41.	ग्रामीण विकास विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र	253/22/2017–बायोगैस	29.05.2024	22875392
42.	केवीआईसी मुंबई, महाराष्ट्र	253/10/2024–बायोगैस	11.06.2024	19920800
43.	त्रिपुरा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, अगरतला	253/4/2024–बायोगैस	30.07.2024	5331038
44.	एमपीएसएआईडीसी भोपाल, मध्य प्रदेश	253/7/2023–बायोगैस	26.09.2024	10544300
45.	पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए) चंडीगढ़	253/11/2023–बायोगैस	26.09.2024	14500350
46.	ओडिशा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, भुवनेश्वर	253/11/2023–बायोगैस	15.10.2024	2146800
47.	उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा, यूरेडा, देहरादून, उत्तराखंड	253/13/2023–बायोगैस	18.10.2024	5058250
48.	ग्रामीण विकास विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र	253/154/2017–बायोगैस	25.11.2024	47955148
49.	एनडीडीबी, मैरिडा, आनंद, गुजरात	253/28/2023–बायोगैस	11.12.2024	14575350
50.	ग्रामीण विकास विभाग, गांधीनगर, गुजरात	253/12/2024–बायोगैस	12.12.2024	34700
51.	ग्रामीण विकास विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र	253/35/2018–बायोगैस	30.12.2024	41194192
52.	छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायपुर, क्रेडा	253/10/2023–बायोगैस	31.12.2024	4090800
53.	अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	253/3/2024–बायोगैस	31.12.2024	150000
54.	ग्रामीण विकास विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र	253/9/2024–बायोगैस	10.06.2024	71385550

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 183 08-04-2025 23:58:40

क्रम सं	कार्यान्वयन एजेंसी / राज्य	स्वीकृति संख्या	दिनांक	एमएनआरई द्वारा निर्गत (रु.
55.	ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी, उत्तराखंड	253/100/2017-बायोगैस	30.04.2024	4296100
56.	आरडी एवं पीआरडी कर्नाटक	253/55/2017-बायोगैस	21.06.2024	2393390
57.	अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	253/3/2024-बायोगैस	31.12.2024	150000
58.	छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, रायपुर, क्रेडा	253/10/2023-बायोगैस	31.12.2024	4090800
59.	ग्रामीण विकास विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र	253/120/2017-बायोगैस	29.05.2024	3794824
60.	केवीआईसी, मुंबई महाराष्ट्र	253/10/2024-बायोगैस	11.06.2024	1581750
61.	त्रिपुरा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, अगरतला, त्रिपुरा	253/4/2024-बायोगैस	30.07.2024	2763000
62.	आरडी एवं पीआरडी, कर्नाटक	253/164/2017-बायोगैस	24.09.2024	7118050
63.	एमपीएसएआईडीसी, भोपाल, मध्य प्रदेश	253/7/2023-बायोगैस	26.09.2024	1490650
64.	ओडिशा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, भुवनेश्वर	253/11/2024-बायोगैस	15.10.2024	15500
65.	उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा (यूरेडा) देहरादून	253/13/2023-बायोगैस	18.10.2024	1158000
66.	ग्रामीण विकास विभाग, मुंबई महाराष्ट्र	253/154/2017-बायोगैस	25.11.2024	6042486
67.	एनडीडीबी मैरिडा, आनंद , गुजरात	253/28/2023-बायोगैस	11.12.2024	686800
68.	पी एवं ग्रामीण विकास विभाग, पश्चिम बंगाल	253/12/2024-बायोगैस	12.12.2024	100000
69.	छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, रायपुर, क्रेडा	253/10/2023-बायोगैस	31.12.2024	292600
70.	ग्रामीण विकास विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र	253/9/2024-बायोगैस	10.06.2024	6419600
71.	ग्रामीण विकास विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र	253/22/2017-बायोगैस	29.05.2024	7569935
72.	केवीआईसी, मुंबई, महाराष्ट्र	253/10/2024-बायोगैस	11.06.2024	987000
73.	ग्रामीण विकास विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र	253/9/2024-बायोगैस	10.06.2024	6935900
74.	मेघालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, शिलांग, मेघालय	253/22/2019-बायोगैस	21.06.2024	957000
75.	एमपीएसएआईडी, भोपाल, मध्य प्रदेश	253/7/2023- बायोगैस	26.09.2024	7302740
76.	ओडिशा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, भुवनेश्वर	253/11/2024-बायोगैस	15.10.2024	15500
77.	उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा (यूरेडा), देहरादून	253/13/2023-बायोगैस	18.10.2024	174000

क्रम सं	कार्यान्वयन एजेंसी / राज्य	स्वीकृति संख्या	दिनांक	एमएनआरई द्वारा निर्गत (रु.
78.	ग्रामीण विकास विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र	253/154/2017–बायोगैस	25.11.2024	5726608
79.	एनडीडीबी मारिडा, आणंद, गांधीनगर गुजरात	253/28/2023–बायोगैस	11.12.2024	7071800
80.	ग्रामीण विकास विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र	253/35/2018–बायोगैस	30.12.2024	585879
81.	छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, रायपुर, क्रेडा	253/10/2023–बायोगैस	31.12.2024	1938300
82.	अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	253/3/2024–बायोगैस	31.12.2024	2640000
83.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर	343/2/2021–बायोगैस	15.05.2024	462000
84.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र, पीएयू लुधियाना, पंजाब	256/1/2022–बायोगैस	03.12.2024	2640280
85.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र एमपीयूएटी, उदयपुर, राजस्थान	256/1/2022–बायोगैस	03.12.2024	2557840
86.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र, आईआईटी, भुवनेश्वर, ओडिशा	256/1/2022–बायोगैस	03.12.2024	2640280
87.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र , आईआईटी, गुवाहाटी, असम	256/1/2022–बायोगैस	03.12.2024	2640280
88.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र, डीएवीवी, इंदौर, मध्य प्रदेश	256/1/2022–बायोगैस	03.12.2024	2640280
89.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र, कोयंबटूर, टीएनएयू तमिलनाडु	256/1/2022–बायोगैस	03.12.2024	2640280
90.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र यूएएस बेंगलुरु, कर्नाटक	256/1/2022–बायोगैस	03.12.2024	2722720
91.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र, आईआईटी, दिल्ली	256/1/2022–बायोगैस	03.12.2024	2722720
92.	उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	343/15/2020–बायोगैस	18.07.2024	3020000
93.	उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	343/19/2020–बायोगैस	18.07.2024	2800000
94.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र, टीएनएयू कोयंबटूर, तमिलनाडु	343/12/2019–बायोगैस	18.07.2024	2450000
95.	तेलंगाना राज्य अक्षय ऊर्जा विकास निगम हैदराबाद, तेलंगाना (टीश्रेडको)	343/17/2020–बायोगैस	28.10.2024	5300000

क्रम सं	कार्यान्वयन एजेंसी / राज्य	स्वीकृति संख्या	दिनांक	एमएनआरई द्वारा निर्गत (रु.
96.	बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केंद्र, यूएएस बेंगलुरु, कर्नाटक	343/3/2023–बायोगैस	28.10.2024	34137500
97.	बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केंद्र, यूएएस, बेंगलुरु , कर्नाटक	343/3/2023–बायोगैस	28.10.2024	1968750
98.	बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र, आईआईटी, गुवाहाटी, असम	343/1/2020–बायोगैस	08.11.2024	1700000
99.	तमिलनाडु अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, टीएनएयू	343/62/2017–बायोगैस	16.12.2024	4950000
	कुल			रु 65,28,26,209

दिनांक 31.12.2024 **तक आरई–आरटीडी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी निधियां**

क्रम सं.	फाइल सं.	परियोजना का शीर्षक	परियोजना संस्थान का नाम	दिनांक	स्वीकृति राशि (रु.)
1.	223/2/2019– अपशिष्ट से ऊर्जा–भाग (3)	"रासायनिक उत्पादन के लिए प्लाज्मा पायरोलिसिस प्रौद्योगिकी के माध्यम से बायोमास गैसीकरण"	आईआईटी रुड़की, उत्तराखंड	03.01.2024	29,00,000
2.	353/5/2020– नई तकनीक	लेह में ग्रीन हाइड्रोजन गतिशीलता परियोजनाएं "	एनटीपीसी लिमिटेड नोएडा, यूपी	27.03.2024	5,00,00,000
3.	31/1/2017– सौर अनुसंधान और विकास	"सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा"	सीएसआईआर–राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली	27.03.2024	8,60,00,000
4.	31/14/2015–16/ पीवीएसई– आर एंड डी	"उन्नत पीवी प्रणाली से संचालित ऊर्जा प्रबंधन नियंत्रक आधारित इन्वर्टर का विकास"	वीआईटीएस, हैदराबाद	30.03.2024	7,42,000
5.	313–21/11/2022– सौर अनुसंधान और विकास	"राष्ट्रीय फोटोवोल्टिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र (एनसीपीआरई) - चरण III"	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे	27.08.2024	11,93,00,000
6.	313–21/9/2022– सौर अनुसंधान और विकास	उत्कृष्टता केंद्र का शीर्षक "अल्ट्रा लो हेड और हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइनों का अनुसंधान और विकास तथा लघु हाइड्रो टर्बाइन मॉडलों का प्रदर्शन पूर्वानुमान"	आईआईटी, रुड़की	27.08.2024	3,25,00,000

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 186 08-04-2025 23:58:40

क्रम सं.	फाइल सं.	परियोजना का शीर्षक	परियोजना संस्थान का नाम	दिनांक	स्वीकृति राशि (रु.)
7.	31/2/2019- सौर अनुसंधान और विकास	"लचीले पेरोवस्काइट सौर सेल और मध्यवर्ती मॉड्यूल"	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, पवई, मुंबई	13.11.2024	40,00,000
8.	31/13/2013-14/ पीवीएसई- आर एंड डी	"लचीले (पॉलीमाइड) सब्सट्रेट पर सीजेडटीएस आधारित सौर सेल निर्माण के लिए प्रक्रिया विकसित करना"	केआईआईटी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	18.11.2024	6,35,887
9.	313-21/4/2024- सौर अनुसंधान और विकास	पेरोवस्काइट टेंडेम सौर सेलों का विस्तार (चरण ९)	आईआईटी, बॉम्बे	18.11.2024	3,00,00,000
10.	226/1/2018- एनटी	देश में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए खंभात की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी में मौसम-महासागर माप (लहर, ज्वार, वर्तमान जल स्तर आदि) "	राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई	19.12.2024	36,90,000
11.	350/2/2018- नई तकनीक	"उच्च स्वदेशी सामग्री के साथ 20 किलोवाट कम तापमान पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली (एलटी-पीईएम) ईंधन सेल की डिजाइन और विकास"	एआरसीआई, चेन्नई	28.12.2024	1,50,00,000

Annual Report Hindi_2024-2025_Option 2.indd 188 08-04-2025 23:58:41

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
EW AND RENEWABLE ENERGY

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय